

राहुल गांधी, अब देश का प्रधानमंत्री बनने को तैयार ही नहीं, तत्पर हैं

पहली बार वे अपने जन्म दिन, 19 जून को आयोजित “फंक्शन” में भाग लेने, 18 जून की रात को भारत लौट आए

-रेणु मि्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 20 जून। राहुल गांधी अब वह अनिच्छुक राजनीतिज्ञ नहीं रहे, जैसा उन्हें वर्षों तक बताया जाता रहा है। कांग्रेस के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि अब वह स्वयं को देश के सर्वोच्च पद के लिए तैयार मानते हैं। इससे भी अधिक, अब वह भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए उत्सुक और इच्छुक हैं।

यह परिवर्तन विपक्ष के नेता बनने के बाद आया जब उन्होंने इस पद के साथ आने वाली सत्ता और प्रभाव का अनुभव किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चारों ओर व्याप्त सत्ता की ताकत, पद और प्रतिष्ठा ने भी उन्हें बहुत प्रभावित किया है।

राहुल गांधी का जन्मदिन पार्टी के कई लोगों के लिए आंखें खोलने वाला रहा और अब कांग्रेस के भीतर यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि राहुल अब प्रधानमंत्री पद की ज़िम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं।

राहुल गांधी के लिए उनका जन्मदिन हमेशा एक निजी मामला रहा है। वह अक्सर 19 जून को देश से बाहर रहते थे, न ही कांग्रेसजनों से मिलते थे

- आज से पहले राहुल का जन्म दिवस, एक प्राइवेट मामला होता था तथा 19 जून को प्रायः विदेश में रहते थे, शायद आम कार्यकर्ता से मिलने से कतराने के कारण।
- पर, अब यह हिचकिचाहट खत्म हो गई है तथा पार्टी के कार्यकर्ताओं को सूचित कर दिया गया था कि दोपहर में दो बजे राहुल एआईसीसी में आयेंगे, जन्म दिन पर उनके अभिवादन स्वीकार करने।
- पहली बार राहुल के जन्म दिवस पर दिल्ली के प्रमुख अखबारों में पूरे पृष्ठ के विज्ञापन छपे, राहुल गांधी को जन्म दिन की बधाई देते हुए।
- राहुल गांधी में यह परिवर्तन तब से आया है, जब से वे संसद में “लीडर ऑफ ऑपोज़िशन” (विपक्ष के नेता) बने हैं तथा इस पद से जुड़ी गरिमा, प्रतिष्ठा व अधिकार से काफी प्रभावित हुए हैं तथा जिस प्रकार का रोब, रूतबा व महत्व मोदी को मिला, प्र.मंत्री के रूप में, वे मानते हैं, उन्हें भी मिलना चाहिए।
- वे यह भी मान रहे हैं कि उनका “कास्ट कार्ड” उन्हें प्र.मंत्री पद तक पहुँचायेगा और उनकी प्र.मंत्री की कुर्सी तक की पद यात्रा अब आसान भी हो गई है. क्योंकि मोदी कमज़ोर पड़े हैं, भाजपा व संघ के मतभेदों के कारण तथा नीतीश कुमार की बीमारी व शारीरिक कमज़ोरी के कारण, वे बिहार में ज़रूर जीतेंगे। साथ ही अमेरिका व ट्रंप अब मोदी का उत्तना समर्थन नहीं कर रहे, जो पहले करते थे।

और न ही शुभकामनाएं देने आने वाली भीड़ से।
इस बार सब कुछ बिल्कुल अलग था, जिसने सभी का ध्यान खींचा।
अपने जन्मदिन की पूर्व संध्या पर वह दिल्ली लौटे।

यह वापसी उनकी मां सोनिया गांधी की तबीयत के कारण नहीं थी, क्योंकि उन्हें उसी सुबह अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और राहुल उन्हें घर लाते गए थे।
अप्रत्याशित रूप से वह 24

अकबर रोड स्थित एआईसीसी कार्यालय पहुंचे। उनके आने से पहले संदेश दिया गया था कि वह दोपहर 2 बजे वहां आएंगे। उन्होंने वहां मौजूद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एक्सओम मिशन -4 फिर से स्थगित

चेन्नई, 20 जून। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) की यात्रा पर ले जाने वाले एक्सओम-4 मिशन को फिर से स्थगित कर दिया गया है। यह मिशन 22 जून को निर्धारित था। एक्सओम स्पेस ने शुक्रवार को

- भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु को अंतरिक्ष स्टेशन ले जाने वाला यह मिशन 22 जून को निर्धारित था

एक नवीनतम अपडेट में कहा कि नई लॉन्च तिथि की घोषणा आने वाले दिनों में की जाएगी। मिशन शुरू में 29 मई के लिए निर्धारित किया गया था। मिशन को मौसम, एलओएस रिसाव और अन्य तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से इसे कई बार स्थगित किया है। इस मिशन में आईएसएस में अंतरिक्ष यात्रियों को 14 दिनों तक रहना है और इस अवधि में वे वहां पर 60 अनुसंधान करेंगे। इनमें से सात माइक्रोग्रेविटी अनुसंधान इसरो के हैं। भारत, अमेरिका, हंगरी और पोलैंड की चार अंतरिक्षयात्रियों की टीम अंतरिक्ष यात्रा पर जाने के लिए तैयार है।

इंजन सरकार लगभग हार मान चुकी है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन कांग्रेस लंबे समय से जो तीन माँग कर रही है, वे 65 प्रतिशत आरक्षण को हकीकत बना सकती हैं।
जयराम रमेश ने बिहार आरक्षण कानून को संविधान की नवीं अनुसूची (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या वियतनाम, अफगानिस्तान, क्यूबा और ईरान के असफल प्रयासों से कुछ नहीं सीखा अमेरिका ने?

हर बार अमेरिका असफल हुआ तथा “अग्ली अमेरिकन” की छवि पाई, जो अब तक पूरी तरह नहीं बदल पाई है

- डॉ. सतीश मिश्रा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 20 जून। अमेरिका ने वियतनाम, अफगानिस्तान और उससे भी पहले ईरान में मिली नाकामियों से कोई सबक सीखा है या नहीं- यह चीज राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के इस कदम से तय होगी कि वे अपने सहयोगी इज़राइल और ईरान के बीच पश्चिम एशिया में छिड़े संघर्ष में अमेरिका को झोंकने का फैसला करते हैं या नहीं।
जब यह रिपोर्ट लिखी जा रही थी, तब तक ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि अमेरिका आधिकारिक रूप से इज़राइल के युद्ध में शामिल होगा या नहीं। लेकिन इतिहास गवाह है कि वियतनाम, अफगानिस्तान, क्यूबा और यहां तक कि ईरान में भी अमेरिका की दखलअंदाजी ने उलटा असर डाला और अमेरिका की छवि ”अहंकारी

- अमेरिका के सी.आई.ए. व ब्रिटेन की इंटीलिजेंस एजेंसी एम.आई.सिक्स ने इन प्रयासों की शुरुआत 1953 में ही कर दी थी। प्रजातंत्रीय तरीके से चुनी गई प्र.मंत्री मोहम्मद मोसद्देग की सरकार को अपदस्थ करके, शाहे मोहम्मद रिज़ा पहलवी को पुनः गद्दी पर स्थापित करके।
- चुनी गई सरकार को अपदस्थ करने का प्रमुख कारण था, ईरान की जमीन के नीचे ऑयल का अपार भंडार।
- यह ही कारण था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के हाथों में “ऑयल भंडार” न पहुँचे, इसे रोकने के लिए अमेरिका व ब्रिटेन ने सोवियत यूनियन के लिए एक “सप्लाय कोरिडोर” बनाया था।
- पर, 1951 में मोसद्देग की निर्वाचित सरकार ने संसद में विधेयक पास कर, ईरान की ऑयल इण्डस्ट्री का नैशलनाइज़ेशन कर, अमेरिका व ब्रिटेन की योजना को फेल कर दिया था।

सरकारों-अमेरिका और ब्रिटेन-ने एक निर्वाचित सरकार को गिरा कर राजतंत्र बहाल किया- और उसे अपनी जनता

विशाखापट्टनम में योग करेंगे प्र.मंत्री

नयी दिल्ली, 20 जून। देश और दुनिया भर में कल 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जायेगा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में सामूहिक योग कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे तीन लाख से अधिक लोगों के साथ योगासन करेंगे।
राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय आ्युष राज्य मंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव

- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित योग संगम कार्यक्रम में प्रधानमंत्री तीन लाख लोगों के साथ योग करेंगे। देश भर में दस लाख से अधिक स्थानों पर योग संगम से तालमेल कर योगाभ्यास किया जाएगा।

जाघव और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू भी शामिल होंगे। विशाखापत्तनम में आयोजित इस कार्यक्रम में ‘योग संगम’ पहल के तहत देश भर में 1० लाख से अधिक स्थानों के साथ एक साथ योग किया जाएगा।
यह कार्यक्रम सुबह साढ़े छह बजे शुरू होगा और पौने आठ बजे संपन्न होगा। इसमें देश भर से अभूतपूर्व भागीदारी की उम्मीद है। देश में विभिन्न जगहों पर आयोजित सत्रों में दो करोड़ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इज़रायल खुशी मना रहा है, ईरान की हवाई युद्ध लड़ने की ताकत पर पूरी तरह छा कर

पर, विश्व इस प्रमुख ऑयल इण्डस्ट्री पर कुप्रभाव की कल्पना करके कांप रहा है

- सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 20 जून। पिछले दो हफ्तों में अपने व्यापक हवाई अभियान के जरिए, इज़रायल ने वह हासिल कर लिया है जिसे कई लोग असंभव मानते थेः ईरान का 90 प्रतिशत लॉन्गेंरेंज एयर डिफेंस सिस्टम निष्क्रिय कर दिया है और लगभग आधी मिसाइल लॉन्चिंग क्षमता को बेअसर कर दिया गया है। लेकिन जहाँ तेल अवीव इस सैन्य सफलता का जश्न मना रहा है, वहीं दुनिया एक और खतरे के लिए तैयार हो रही है, एक अस्थिर मिडिल ईस्ट और आसमान छूती तेल की कीमतें, जो वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को झटका दे सकती हैं।
इज़रायली हवाई हमलों की पहली लहर के साथ ही तेल बाज़ारों में तुरंत प्रतिक्रिया देखी गई। ब्रैट क्रूड की कीमत 90 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 1०5 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुँच गई। यह

- कई ऑयल कम्पनियों ने अपने टैंकर्स में “स्ट्रेट ऑफ होरमुज़” में जाने से रोक दिए हैं तथा ऑयल के दाम कुछ दिनों में ही 90 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 105 डॉलर प्रति बैरल हो गये हैं।
- इसके अलावा इंश्योरेंस कम्पनियों ने इन टैंकर्स को इन्श्योर करने की कीमत में भी भारी वृद्धि कर दी है।
- साथ ही, यमन हाउथीस, लेबनान के हिजबुल्लाह जैसे समुद्री लुटेरों व आतंकवादियों ने ईरान के कमज़ोर पड़ जाने के बाद अपनी गतिविधियाँ बढ़ा दी हैं।
- सभी आशंकित हैं, यह अनिश्चितता क्या कहर धायेगी। इसका अंदाज़ा लगाना ही कठिन है।

उछाल सिर्फ ईरानी तेल निर्यात में रुकावट के कारण नहीं है, जो पहले से ही प्रतिबंधों के तहत है, बल्कि यह भविष्य को लेकर गहराते भय का संकेत है। ईरान ने होरमुज़ जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होरमुज़) को बंद करने की

केप ऑफ गुड होप के जरिए लंबा और महंगा रास्ता लेना पड़ा है।
इस चिंता को खाड़ी क्षेत्र से होकर गुज़रने वाले जहाज़ों के लिए बीमा प्रीमियम में अचानक हुई वृद्धि ने और बढ़ा दिया है।कई प्रमुख शिपिंग कंपनियां ने इस क्षेत्र में परिचालन रोक दिया है, और तेल कंपनियाँ डिलीवरी में देरी की सूचना दे रही हैं। इसके जवाब में, अमेरिका, भारत और चीन अपने रणनीतिक तेल भंडार से तेल जारी करने पर विचार कर रहे हैं, ताकि, स्थिति को कुछ समय के लिए संभाला जा सके। लेकिन ये उपाय केवल अस्थायी राहत दे सकते हैं। अगर सैन्य संघर्ष और तेज़ हुआ, या फिर, ईरान समर्थित लड़ाकों ने सऊदी अरब या यूएई के तेल द्वांचों पर हमला किया तो दुनिया एक गंभीर आपूर्ति संकट का सामना कर सकती है।
रणनीतिक परिणाम भी उतने ही चिंताजनक है। इज़रायल ने ईरान का (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पासपोर्ट आवेदन के लिए पति के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं

चेन्नई, 20 जून। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि किसी महिला को पासपोर्ट के लिए आवेदन करने से पहले अपने पति की अनुमति लेने या उसके हस्ताक्षर करवाने की जरूरत नहीं है। जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ने यह फैसला हाल ही

- मद्रास हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता रेवती की याचिका पर यह फैसला दिया और पासपोर्ट कार्यालय को पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया।

में रेवती नाम की महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। रेवती ने अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी कि वे उनके पति के हस्ताक्षर की अनिवार्यता के बिना ही एक नया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

सफलता का केवल एक ही रहस्य है, साधारण चीजों को असाधारण तरीके से करना। –जॉन डी. रॉकफेलर

राजस्थान: आर.जी.एच.एस. पेंशनरों को परेशानी, सरकार की उदासीनता

RGHS राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों, विधायकों, पूर्व विधायकों और अन्य पात्र लाभार्थियों को नकद रहित चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करना है। सितंबर 2021 में शुरू हुई यह योजना सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) की तर्ज पर तैयार की गई थी। इसका लक्ष्य लगभग 13 लाख सरकारी कर्मचारियों कके परिवारों को, जिसमें 8 लाख सरकारी कर्मचारी और 3.28 लाख पेंशनर शामिल हैं, उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना रहा है। योजना के तहत नकद रहित उपचार, प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का वार्षिक कवरेज (गंभीर बीमारियों के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपये), आउटडोर मरीजों (OPD) के लिए 20,000 रुपये की सीमा, और इनडोर मरीजों (IPD) के लिए कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है। लेकिन इसके बावजूद, पेंशनरों को इस योजना के तहत कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो इसकी उपयोगिता को कम कर रहा है। पेंशनरों की समस्याओं की लगातार अनदेखी सरकारी उदासीनता, घोटालों पर घोटालों ने इसकी विश्वसनीय को हिलाकर रख दिया है। सरकार को समस्ता जानकारी है लेकिन कोई इस पर प्रामाणिक चर्चा के लिए तैयार नहीं है । होना यह चाहिए कि योजना के परिमार्जन हेतु अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करते हुए इसे विश्वसनीय बनाया जाए। पेंशनरसँ इस समाज में सरकार के अघोषित और अवैतनिक एम्बेसडर हैं सरकार को प्राथमिकता में इन्हें सर्वोच्च स्थान मिलना चाहिए। पेंशनरों की समस्याएँ उण् के कार्यान्वयन में कई खामियों को सिद्ध से उजागर कर रही हैं। पहली और सबसे बड़ी समस्या दवाइयों की अनुपलब्धता है। पैनल में शामिल फार्मसी स्टोर्स पर जीवन रक्षक और नियमित दवाएँ अक्सर उपलब्ध नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए, बारां और कोटा जैसे जिलों में पेंशनरों ने बताया कि फार्मसी स्टोर्स ने RGHS के तहत दवाएँ देना बंद कर दिया, क्योंकि सरकार ने उनके बकाया भुगतानों में महीनों की देरी की है। एक रिपोर्ट के अनुसार, RGHS के तहत फार्मसी स्टोर्स के 500 करोड़ रुपये से अधिक के बिल लॉबी पड़े हैं। इससे पेंशनरों को निजी तौर पर दवाएँ खरीदनी पड़ रही हैं, जो उनकी सीमित पेंशन आय पर भारी बोझ डाल रहा है। कई बुजुर्ग पेंशनरों ने अपनी बचत खर्च करने या गहने बेचने की शिकायत की है, खासकर मधुमेह, उच्च रक्तचाप, और हृदय रोग जैसी पुरानी बीमारियों के इलाज के लिए। दूसरी प्रमुख समस्या नकद रहित सुविधा का वास्तविकता में लागू न होना है। RGHS का दावा है कि यह योजना लाभार्थियों को सरकारी और पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में नकद रहित उपचार प्रदान करती है। जबकि पेंशनरों को शिकायत की है कि अनेक अस्पताल कैशलेस सुविधा प्रदान नहीं करते और उन्हें इलाज के लिए पहले नकद भुगतान करना पड़ता है। इसके बाद प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया इतनी जटिल और समय लेने वाली है कि कई बुजुर्ग इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाते।

जयपुर के एक 75 वर्षीय पेंशनर ने बताया कि उनके हृदय शल्य चिकित्सा के लिए 3 लाख रुपये का बिल निजी तौर पर चुकाना पड़ा, और प्रतिपूर्ति के लिए दावा जमा करने के बावजूद भुगतान नहीं मिला। यह प्रक्रिया विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के पेंशनरों के लिए और भी कठिन है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म और कागजी कार्रवाइयों से परिचित नहीं हैं उनकी हालत बहुत खराब है। वृद्धावस्था में दंत समस्या सबसे अधिक गम्भीर होती है लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दंत चिकित्सा और इससे जुड़ी अन्य सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं को RGHS के दायरे से बाहर रख छोड़ा है। पेंशनरों, विशेष रूप से वृद्धों, को दंत समस्याओं जैसे रूट केनाल, डेन्चर, या दाँतों की सफाई के लिए निजी क्लीनिकों पर निर्भर रहना पड़ता है। सरकार ने दंत चिकित्सा पर नाम मात्र की आपूर्ति का प्रावधान कर छोड़ा है। आज अगर एक वृद्ध व्यक्ति को यदि अपने दाँतों का पूरा ढांचा लगवाना पड़े तो दो से तीन लाख रुपए खर्च करने होंगे सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसके अलावा, कुछ विशेष जाँचें जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, या कैसर स्क्रॉनिंग भी कई अस्पतालों में RGHS के तहत कवर नहीं होती। इससे पेंशनरों को अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ता है।

उदाहरण के लिए, एक पेंशनर ने बताया कि उनकी कैसर स्क्रॉनिंग की लागत RGHS में शामिल नहीं थी, जिसके लिए उन्हें 50,000 रुपये निजी तौर पर खर्च करने पड़े। इसी तरह पैनल में शामिल अस्पतालों की अपर्याप्त सुविधाएँ और अनावश्यक जाँचें हैं। कई निजी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं जैसे पर्याप्त बेड, विशेषज्ञ डॉक्टर, या उन्नत उपकरणों की कमी है। इसके विपरीत, कुछ अस्पताल अनावश्यक जाँचें और लंबे समय तक भर्ती करके RGHS फंड का दुरुपयोग करते हैं। जयपुर के एक निजी अस्पताल में एक पेंशनर को सामान्य बुखार के लिए 10 दिन तक भर्ती रखा गया और 28 जाँचें की गईं, जो चिकित्सकीय रूप से अनावश्यक थीं। यह न केवल पेंशनरों के लिए

परेशानी का कारण बनता है, बल्कि योजना के संसाधनों का दुरुपयोग भी करता है। सरकारी अस्पतालों में भी स्थिति बेहतर नहीं है, जहाँ बेड की कमी, लंबी प्रतीक्षा अवधि, और विशेषज्ञ डॉक्टरों की अनुपस्थिति आम समस्याएँ हैं। पेंशनरसं के प्रतिपूर्ति प्रक्रिया में देरी और अस्वीकृति है जो उनके लिए बड़ी परेशानी का कारण है। जब पेंशनरों को नकद भुगतान करना पड़ता है, तो वे ऑनलाइन RGHS पोर्टल के माध्यम से दावा जमा करते हैं। जिसमें अनेक मामलों में दावे तकनीकी कारणों जैसे अपूर्ण दस्तावेज या अस्पष्ट नियमों के कारण अस्वीकार कर दिए जाते हैं। 2024 में एक सर्वेक्षण में पाया गया

कि RGHS के तहत 30% से अधिक दावे 3–6 महीने से अधिक समय तक लंबित रहते हैं। यह देरी पेंशनरों के लिए वित्तीय तनाव का कारण बनती है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले ही इलाज पर अपनी बचत खर्च कर चुके हैं। सरकारी उदासीनता ने इन समस्याओं को और गंभीर किया है। सबसे पहले, बकाया भुगतानों में देरी ने फार्मसी स्टोर्स और अस्पतालों को उण् के हहत सेलएँ देने से हतोत्साहित किया है। 2024 तक, अनुमानित 500 करोड़ रुपये के बिल लंबित थे, जिसके कारण कई अस्पतालों ने कैशलेस सुविधा बंद कर दी। दूसरा, निगरानी तंत्र की कमी ने घोटालों को बढ़ावा दिया है। उदाहरण के लिए, राजस्थान मेंडिजल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 343 करोड़ रुपये का टेंडर घोटाला सामने आया, जिसमें फर्जी बिलिंग और अधिकारियों की मिलीभगत शामिल थी। तीसरा, पेंशनरों के बीच जागरूकता की कमी एक बड़ी समस्या है। कई पेंशनरों को RGHS के नियमों, पात्रता, और प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं है। सरकार ने इसके लिए जागरूकता अभियानों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया। चौथा, RGHS का प्रशासनिक ढांचा बार-बार बदल रहा है, जैसे कि हाल ही में वित्त विभाग से चिकित्सा विभाग को योजना हस्तांतरण की है, जिसने भ्रम और अक्षमता को बढ़ाया है। RGHS में घोटाले इस योजना की विश्वसनीयता को और कम कर रहे हैं। फर्जी बिलिंग एक प्रमुख समस्या है, जिसमें अस्पताल अनावश्यक जाँचें और भर्ती करके RGHS फंड का दुरुपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए एक जांच में पाया गया कि जयपुर और उदयपुर के कुछ अस्पतालों ने सामान्य बीमारियों के लिए 5–10 लाख रुपये के बिल बनाए, जो चिकित्सकीय रूप से अनुचित थे। इसके अलावा, 2000 करोड़ रुपये के फर्जी बिलों का मामला सामने आया, जिसमें दवाइयों और उपकरणों के लिए फर्जी टेंडर शामिल थे। इन घोटालों में अधिकारियों, डॉक्टरों, और निजी कंपनियों की मिलीभगत की बात सामने आई है। नकली दवाएँ और फार्मसी स्टोर्स पर जीवन रक्षक दवाओं की अनुपलब्धता ने भी पेंशनरों का विश्वास तोड़ा है। इन समस्याओं के समाधान के लिए एनमिलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला, प्रशासनिक सुधार जरूरी है। एक स्वतंत्र निगरानी समिति का गठन किया जाए, जिसमें चिकित्सा विशेषज्ञ, पेंशनर प्रतिनिधि, और ऑडिटर शामिल हों। यह समिति नियमित रूप से अस्पतालों और फार्मसी स्टोर्स की जाँच करे। अस्पतालों और स्टोर्स को समय पर भुगतान के लिए एक ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया जाए। दूसरा, पेंशनरों की सुविधा के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएँ, जिसमें हिंदी में सरल जानकारी उपलब्ध कराई जाए। प्रत्येक जिले में RGHS शिक्षावत निवारण केंद्र स्थापित किए जाएँ, और मौजूदा हेल्पलाइन (181) को और प्रभावी बनाया जाए। दंत चिकित्सा और विशेष जाँचों को RGHS के दायरे में शामिल किया जाए। तीसरा, घोटालों की रोकथाम के लिए ऑनलाइन ऑडिट सिस्टम लागू किया जाए, जिसमें AI और मशीन लर्निंग का उपयोग हो। फर्जी बिलिंग में शामिल अस्पतालों को पैनल से हटाया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। चौथा, RGHS पोर्टल और मोबाइल ऐप को बुजुर्गों के लिए सरल बनाया जाए, जिसमें हिंदी भाषा और वॉयस कमांड का विकल्प हो। एक डिजिटल ई-वॉलेट सिस्टम शुरू किया जाए, जिसमें पेंशनरों के चिकित्सा रिकॉर्ड और शेष राशि की जानकारी हो। इसी प्रकार अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाएँ RGHS को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं।

केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) में देश भर में 300 से अधिक शहरों में पैनल अस्पतालों का व्यापक नेटवर्क है। RGHS को भी अन्य राज्यों में अस्पतालों का विस्तार करना चाहिए। CGHS की तरह ऑनलाइन दवा वितरण शुरू किया जाए। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना (CMCHIS) में ऑनलाइन दावा ट्रैकिंग और त्वरित निपटन की प्रणाली है, जिसे RGHS में लागू किया जा सकता है। तमिलनाडु का PPP मॉडल भी अस्पतालों की संख्या बढ़ाने में उपयोगी हो सकता है। केरल की करुणा स्वास्थ्य योजना में गंभीर बीमारियों के लिए विशेष कवरेज और सामुदायिक भागीदारी के उदाहरण अपनाए जा सकते हैं। दिल्ली की आयुष्मान भारत योजना में मोबाइल स्वास्थ्य क्लीनिक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। स्पष्ट है कि RGHS में पेंशनरों की समस्याएँ, जैसे दवाइयों की अनुपलब्धता, नकद रहित सुविधा का अभाव, और घोटाले, इस योजना की कमजोरियों को दर्शाते हैं। सरकारी उदासीनता ने इन समस्याओं को और बढ़ाया है। प्रशासनिक सुधार, तकनीकी क्अनयन, और अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर RGHS को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। यह योजना पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा बन सकती है, बशर्ते सरकार इन समस्याओं को गंभीरता से ले और त्वरित कदम उठाए। पेंशनरसं के प्रति सरकार का सौहार्द पूर्ण रवैया स्वयं सरकार की शाख को बढ़ाने वाला होगा। वरिष्ठ नागरिकों की हिफाजत और उनका सम्मान किसी भी समाज की संवेदनशीलता का प्रमाण होता है आशा है सरकार इस दिशा में समुचित कदम उठाएगी।

–अतिथि सम्पादक,

राजेन्द्र मोहन शर्मा,

वरिष्ठ साहित्यकार शिक्षाविद् और चिन्तक



सौरभ सिंगारिया

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि प्रदेश में जल की कमी न हो, उसका संरक्षण और संग्रहण किया जाए जिससे प्रदेश खुशहाल बने, साथ ही प्रदेश में वृहद स्तर पर पौधारोपण किया जाए जिससे कि प्रदेश हरा-भरा बने।

इसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए राज्य में ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 5 जून, 2025 से प्रारंभ किया है जिसमें जल संरक्षण संठाहण, पर्यावरण संरक्षण व पौधारोपण , स्वच्छता और इसके लिये जागरूकता को महत्व दिया है।

जवाई बांध – पाली की लाइफलाइन :-इस बांध का शिलान्यास जोगपुर महाराजा उम्मेदसिंह द्वारा 13 मई, 1946 को किया गया था। परियोजना की कुल लागत 2.60 करोड़ रुपये थी। बांध निर्माण कार्य 1957 में पूर्ण हुआ।

म्यूचुअल फंड्स को भी डीमैट में लाना क्यों ज़रूरी है?



सुरील दत्त गोयल

भारत में पूंजी बाजार लगातार विकसित हो रहा है। भारतीय वित्तीय बाजार में डिजिटलीकरण की क्रांति ने पिछले दशकों में अभूतपूर्व परिवर्तन लाए हैं। टेक्नोलॉजी, पारदर्शिता और निवेशकों के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) और सरकार ने समय-समय पर कई दूरदर्शी निर्णय लिए हैं। स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध सभी सिस्कोयोरिज्ड को 100% डीमैट (हिमैटेरियलाइज्ड) फॉर्मेट में लाना ऐसा ही एक कदम था, जिसने शेयर बाजार में धोखाधड़ी की संभावनाओं को कम किया और लेनदेन को त्वरित एवं पारदर्शी बनाया। सेबी और सरकार डिजिटलीकरण का हिंदोरा तो पीटती हैं, मगर म्यूचुअल फंड्स के मामले में जानबूझकर पिछड़ावन क्यों बनाए हुए हैं? शेयरों और प्राइवेट कंपनी शेयरों को डीमैट में बदलकर उन्होंने दिखा दिया कि वे जानते हैं कि कैसे धोखाधड़ी रोकी जाती है। फिर इस 72 लाख करोड़ के एक महत्वपूर्ण निवेश के साधन म्यूचुअल फंड्स को डीमैट में अनिवार्य करने की दिशा में अब तक कदम क्यों नहीं उठाया गया? क्या यह जानबूझकर की गई लापरवाही है?

राशिफल शनिवार 21 जून, 2025



पंडित अनिल शर्मा

आषाढ मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, शनिवार, विक्रम संवत 2082, अश्विनी नक्षत्र सायं 7:50 तक, अविगंड योग रात्रि 8:29 तक, विष्टिकरण प्रातः 7:19 तक, चन्द्रमा आज मेष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मिथुन, चन्द्रमा-मेष, मंगल-सिंह, बुध-मिथुन, गुरू-मिथुन, शुक्र-मेष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज भद्रा प्रातः 7:19 तक है। सायन कर्क में सूर्य प्रवेश प्रातः 8:12 पर होगा। आज योगिनी एकादशी व्रत स्मार्तों का है। आज एकादशी तिथि का क्षय हुआ है। आज सूर्य दक्षिणायन आरम्भ होगा। वर्षा ऋतु आरम्भ होगी।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ 7:20 से 9:03 तक, चर 12:38 से 2:11 तक, लाभ-अमृत 2:11 से 5:36 तक।

राहूकाल: 9:00 से 10:30 तक। **सूर्योदय** 5:37, **सूर्यास्त** 7:19

निर्माण के बाद 1973 में प्रथम बार गेट खोल कर पानी की निकासी की गई एवं बांध का गेज 60.00 फिट से बढ़ाकर 61.25 फीट किया गया।

बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिये वर्ष 1969 से 1978 के मध्य सेई अपवर्तन योजना का कार्य किया गया। सेई बांध से 6776 मीटर लम्बी सुरंग के माध्यम से जवाई बांध में पानी का अपवर्तन प्रारम्भ किया गया। वर्ष 2006 के दौरान सेई बांध की उचाई 8.25 मीटर से बढ़ाकर 10.93 मीटर की गई जिसमें जवाई बांध को अतिरिक्त 516 मीट्रिक घन फीट पानी उपलब्ध हो सका। निर्माण के 63 वर्षों में अब तक अब तक जवाई बांध मात्र 9 बार ही पूर्ण भरा एवं वर्ष 1973 से 2017 के बीच आठ बार जवाई बांध के गेट खोलकर पानी को जवाई नदी में छोड़ा गया।

पेयजल में प्रमुख क़्रोत :- जवाई बांध से वर्तमान में सिराही जिले के शिवगंज कस्बे एवं पाली जिले के शहरों समेत 9 कस्बों सुमेरपुर, देसूरी, रानी, जैतारण, माक्वाड़ जंक्शन, रायपुर, रोहट, सोजत व बाली तथा 985 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

सिंचाई से किसानों को लाभ :- जवाई बांध से 57 गांवों के 38671.00 हैक्टेयर (पाली जिले के 33 गांव एवं जालौर जिले के 24 गांवों के 38600 किसान सिंचाई सुविधा से लाभान्वित होते है।

नहरों की स्थिति :- जवाई कमाण्ड क्षेत्र में मुख्य नहर 23.10



किमी. लम्बी है। इस नहर की 5 वितरिकाएँ हैं, जिनकी लम्बाई 133.30 किमी. एवं 16 माइनर नहरों की लम्बाई 97.40 किमी. है। इनके द्वारा कुल 233.80 किमी. लम्बाई की पक्की नहरों द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

जल संगम :- जवाई कमाण्ड क्षेत्र में सरकार व किसानों के बीच तालमेल व सिंचाई में सरकार की ओर से पारदर्शिता के लिये किसानों के लिये 15 जल उपभोक्ता संगम है। इनके सहयोग

से जल वितरण समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव व निर्णयों के अनुसार टेल से हेड तक खसरो के क्षेत्रफल के अनुसार काश्तकारों को समय आवॉरिट कर बाराबंदी व्यवस्था से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

जवाई बांध में पानी लाने वाली सेई बांध की सुरंग को 1.5 मीटर गहरा करने हेतु कार्य प्रगति पर है। इस कार्य के बाद जवाई को 840 मीट्रिक घन फीट प्रतिवर्ष अतिरिक्त पानी उपलब्ध होगा।

वर्तमान में जवाई का जल स्तर 60 फीट है। जवाई बांध और इसके आसपास का क्षेत्र पिछले कुछ समय से देश के पर्यटन मानचित्र पर नया सितारा बनकर उभरा है। जवाई लेपर्ड सवारी देश-विदेश के सेलिब्रिटी के बीच आकर्षण का केन्द्र बना है जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में जबर्दस्त परिवर्तन आया है।

सौरभ सिंगारिया

सहायक निदेशक, पाली

सूचना एवं जनसंपर्क

विभाग, राजस्थान

म्यूचुअल फंड्स को भी डीमैट में लाना क्यों ज़रूरी है?

देश की एसेट मैनेजमेंट कंपनियां (ए एम सी) करोड़ों निवेशकों का पैसा संभालती हैं। एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट (एयूएम) 72.20 लाख करोड़ तक पहुँच गया है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि म्यूचुअल फंड्स अब भारतीय निवेशकों के बीच कितने लोकप्रिय हो गए हैं। इतने बड़े बाजार के लिए एक समान, पारदर्शी और कुशल प्रणाली की आवश्यकता है।

डीमैट फॉर्मेट के लाभ
म्यूचुअल फंड्स को अनिवार्य रूप से डीमैट फॉर्मेट में लाने से कई महत्वपूर्ण लाभ होंगे:
निवेशकों के लिए लाभ
1. **रियल-टाइम ट्रॉन्ज़ैक्शन:** निवेशक तुरंत ऑनलाइन रिडेम्प्शन और खरीद कर सकेंगे, जिससे उन्हें उसी दिन का नवीनतम मूल्य मिलेगा, बिना एक दिन का इंतज़ार किए।

2. **एकीकृत पोर्टफोलियो**
दृश्य: निवेशक अपने सभी निवेशों – शेयर, बांड और म्यूचुअल फंड्स – को एक ही डीमैट अकाउंट में देख सकेंगे, जिससे पोर्टफोलियो प्रबंधन आसान होगा।
3. **पेपरवर्क में कमी:** डीमैट फॉर्मेट में म्यूचुअल फंड्स रखने से भौतिक दस्तावेजों या पेपरवर्क की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।समस्त कार्य पेपर लेस होने की वजह से माननीय मोदी सरकार का डिजिटल इंडिया का सपना साकार होता है ।

बाजार के लिए लाभ
1. **बाजार में वॉल्यूम वृद्धि:** म्यूचुअल फंड्स को ट्रेडेबल बनाने से बाजार में वॉल्यूम में तुरंत प्रभाव से वर्तमान मूल्यांकन के हिसाब से बेहतर 72 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक की उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

2. **राँग सेलिंग पर लगाम:** एजेंट्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा स्कीम की गलत बिक्री की संभावनाएँ खत्म हो जाएँगी।
3. **बोकर्स के लिए अवसर:** शेयर बाजार के ब्रोकर्स के पास बड़ा वॉल्यूम आएगा, जिससे उनके व्यवसाय में वृद्धि होगी।

4. **डिजिटल परिवर्तन:** पूरा म्यूचुअल फंड सिस्टम डिजिटल हो जाएगा, जिससे भारत के डिजिटल वित्तीय परिवर्तन को बढ़ावा मिलेगा।
फंड मैनेजर्स के लिए लाभ
फंड मैनेजर्स पर दैनिक रिडेम्प्शन और नए निवेश के मानसिक दबाव से मुक्ति मिलेगी। रिडेम्प्शन के दबाव से मुक्त होकर वे बेहतर और दीर्घकालिक रणनीतियों पर काम कर पाएंगे, जिससे उनके निवेश निर्णय बेहतर होंगे।

कार्यान्वयन का प्रस्तावित मॉडल
म्यूचुअल फंड्स को ट्रेडेबल बनाने के लिए एक मॉडल प्रस्तावित किया जा सकता है:-
1. **एनएसई का म्यूचुअल फंड सर्विस सिस्टम (एमएफएसएस):** एनएसई पहले से ही एमएफएसएस प्रदान करता है, इसी प्रकार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बीएसई स्टार, जिसके माध्यम से निवेशक म्यूचुअल फंड यूनित्स खरीद और बेच सकते हैं। इस प्रणाली को विस्तारित करके सभी म्यूचुअल फंड्स के लिए अनिवार्य किया जा सकता है।

2. **डेली एनएवी के आधार पर ट्रेडिंग:** जैसे आरबीआई हर दिन विदेशी मुद्राओं के लिए रेट तय करता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड कंपनियाँ हर शाम अपनी एनएवी घोषित करती हैं। इसी एनएवी के आधार पर अगले दिन की ट्रेडिंग हो सकती है।

3. **डिपॉजिटरी सिस्टम का उपयोग:** एनएसडीएल और सीएसडीएल जैसे डिपॉजिटरीज पहले से ही म्यूचुअल फंड यूनित्स को डीमैट फॉर्म में रखने की सुविधा प्रदान करते हैं। इस व्यवस्था को अनिवार्य बनाया जा सकता है।

सरकार और सेबी से अपेक्षा
जब सेबी ने लिस्टेड सिस्कोरिटीज और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लिए डीमैट फॉर्मेट अनिवार्य कर दिया है, तो समय आ गया है कि सरकार और सेबी सभी स्टैकहोल्डर्स से चर्चा कर इस महत्वपूर्ण सुधार को लागू करें। म्यूचुअल फंड्स को अनिवार्य डीमैट फॉर्मेट में लाकर भारत के शेयर बाजार को पारदर्शिता, तरलता और निवेशकों के विश्वास का नया आधार दिया जाए। यह न केवल निवेशकों के लिए सुविधाजनक होगा, बल्कि पूरे वित्तीय बाजार के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। सरकार और सेबी को सभी हिस्धारकों – एसेट मैनेजमेंट कंपनियों, स्टॉक एक्सचेंजों, डिपॉजिटरीज और निवेशकों – के साथ मिलकर इस परिवर्तन को लागू करने के लिए एक रोडमैप तैयार करना चाहिए। यह कदम भारतीय वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता, कुशलता और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देगा, जिससे अंततः निवेशकों का कल्याण होगा। भारत के वित्तीय बाजारों में यह परिवर्तन एक नए जीवन, नए युग और नई दिशा की शुरुआत होगी, जो हमारे देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

कार्यान्वयन का प्रस्तावित मॉडल
म्यूचुअल फंड्स को ट्रेडेबल बनाने के लिए एक मॉडल प्रस्तावित किया जा सकता है:-
1. **एनएसई का म्यूचुअल फंड सर्विस सिस्टम (एमएफएसएस):** एनएसई पहले से ही एमएफएसएस प्रदान करता है, इसी प्रकार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बीएसई स्टार, जिसके माध्यम से निवेशक म्यूचुअल फंड यूनित्स खरीद और बेच सकते हैं। इस प्रणाली को विस्तारित करके सभी म्यूचुअल फंड्स के लिए अनिवार्य किया जा सकता है।

2. **डेली एनएवी के आधार पर ट्रेडिंग:** जैसे आरबीआई हर दिन विदेशी मुद्राओं के लिए रेट तय करता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड कंपनियाँ हर शाम अपनी एनएवी घोषित करती हैं। इसी एनएवी के आधार पर अगले दिन की ट्रेडिंग हो सकती है।

सरकार और सेबी से अपेक्षा
जब सेबी ने लिस्टेड सिस्कोरिटीज और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लिए डीमैट फॉर्मेट अनिवार्य कर दिया है, तो समय आ गया है कि सरकार और सेबी सभी स्टैकहोल्डर्स से चर्चा कर इस महत्वपूर्ण सुधार को लागू करें। म्यूचुअल फंड्स को अनिवार्य डीमैट फॉर्मेट में लाकर भारत के शेयर बाजार को पारदर्शिता, तरलता और निवेशकों के विश्वास का नया आधार दिया जाए। यह न केवल निवेशकों के लिए सुविधाजनक होगा, बल्कि पूरे वित्तीय बाजार के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। सरकार और सेबी को सभी हिस्धारकों – एसेट मैनेजमेंट कंपनियों, स्टॉक एक्सचेंजों, डिपॉजिटरीज और निवेशकों – के साथ मिलकर इस परिवर्तन को लागू करने के लिए एक रोडमैप तैयार करना चाहिए। यह कदम भारतीय वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता, कुशलता और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देगा, जिससे अंततः निवेशकों का कल्याण होगा। भारत के वित्तीय बाजारों में यह परिवर्तन एक नए जीवन, नए युग और नई दिशा की शुरुआत होगी, जो हमारे देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

कार्यान्वयन का प्रस्तावित मॉडल
म्यूचुअल फंड्स को ट्रेडेबल बनाने के लिए एक मॉडल प्रस्तावित किया जा सकता है:-
1. **एनएसई का म्यूचुअल फंड सर्विस सिस्टम (एमएफएसएस):** एनएसई पहले से ही एमएफएसएस प्रदान करता है, इसी प्रकार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बीएसई स्टार, जिसके माध्यम से निवेशक म्यूचुअल फंड यूनित्स खरीद और बेच सकते हैं। इस प्रणाली को विस्तारित करके सभी म्यूचुअल फंड्स के लिए अनिवार्य किया जा सकता है।

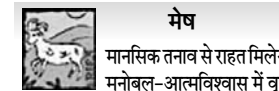
2. **डेली एनएवी के आधार पर ट्रेडिंग:** जैसे आरबीआई हर दिन विदेशी मुद्राओं के लिए रेट तय करता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड कंपनियाँ हर शाम अपनी एनएवी घोषित करती हैं। इसी एनएवी के आधार पर अगले दिन की ट्रेडिंग हो सकती है।

कार्यान्वयन का प्रस्तावित मॉडल
म्यूचुअल फंड्स को ट्रेडेबल बनाने के लिए एक मॉडल प्रस्तावित किया जा सकता है:-
1. **एनएसई का म्यूचुअल फंड सर्विस सिस्टम (एमएफएसएस):** एनएसई पहले से ही एमएफएसएस प्रदान करता है, इसी प्रकार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बीएसई स्टार, जिसके माध्यम से निवेशक म्यूचुअल फंड यूनित्स खरीद और बेच सकते हैं। इस प्रणाली को विस्तारित करके सभी म्यूचुअल फंड्स के लिए अनिवार्य किया जा सकता है।

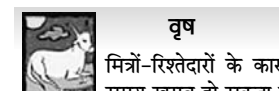
2. **डेली एनएवी के आधार पर ट्रेडिंग:** जैसे आरबीआई हर दिन विदेशी मुद्राओं के लिए रेट तय करता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड कंपनियाँ हर शाम अपनी एनएवी घोषित करती हैं। इसी एनएवी के आधार पर अगले दिन की ट्रेडिंग हो सकती है।

कार्यान्वयन का प्रस्तावित मॉडल
म्यूचुअल फंड्स को ट्रेडेबल बनाने के लिए एक मॉडल प्रस्तावित किया जा सकता है:-
1. **एनएसई का म्यूचुअल फंड सर्विस सिस्टम (एमएफएसएस):** एनएसई पहले से ही एमएफएसएस प्रदान करता है, इसी प्रकार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बीएसई स्टार, जिसके माध्यम से निवेशक म्यूचुअल फंड यूनित्स खरीद और बेच सकते हैं। इस प्रणाली को विस्तारित करके सभी म्यूचुअल फंड्स के लिए अनिवार्य किया जा सकता है।

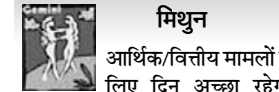
2. **डेली एनएवी के आधार पर ट्रेडिंग:** जैसे आरबीआई हर दिन विदेशी मुद्राओं के लिए रेट तय करता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड कंपनियाँ हर शाम अपनी एनएवी घोषित करती हैं। इसी एनएवी के आधार पर अगले दिन की ट्रेडिंग हो सकती है।



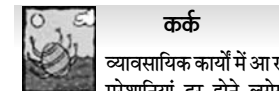
मेघ मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मोनोबल-आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। मन:स्थिति में सुधार होगा। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रहेगा।



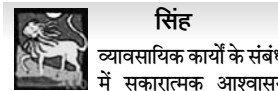
वृष मित्रों-रिश्तेदारों के कारण समय खर्च हो सकता है। व्यक्तिगत कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। मन में अस्तोषता बना रहेगा।



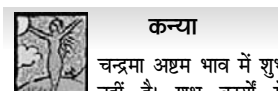
मिथुन आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटक हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।



कर्क व्यावसायिक कार्यों में आ रही परेशानियाँ दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



सिंह व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। घर-परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।



कन्या चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा में दुर्घटना का भय है।

सार-समाचार

**‘प्रशंस्कों की तालियां ही होती हैं
कलाकार की असली पूंजी’**

कोटर, (निर) कतिशाम् दु गुप् ऑफ सोशल अवेरनेस संस्था की कथा को, 17 कला प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। संस्था की अध्यक्ष संस्थेहा श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. नवीन सक्सेना ने अपने उद्बोधन ने कहा कि कला जीवन में कई रंग भरती है आज के युवाओं में इसका महत्व बहुत है। शिक्षावृद्ध नीलम खंडेलवाल ने कहा कि युवाओं को तनाव से दूर रखने का जिम्मा हम सभी का है। इस दिशा में निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। डॉ. मीरा ने कहा कि कलाकार तो कला संपृक्त रहने वाला जीव होता है। प्रशंसकों की तालियाँ ही उसकी असली पूंजी हैं। वरिष्ठ पंडित महोदय वसंत ने कहा कि कलाकारों को अवसर एवं प्रोत्साहन मिलना चाहिए। संस्था की मास्टर ट्रेनर कतिशाम् श्रीवास्तव ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में नाच कला को स्थूल पाठ्यक्रम में जोड़ने की आवश्यकता महसूस होती है। समाज के विकास में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है जिसे नकारा नहीं जा सकता संस्था के उपाध्यक्ष डॉक्टर जी.आर. गोयल ने बताया कि समारोह में सात दिवसीय निःशुल्क कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले नव-संचालकों सहित 17 कलाकारों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का सकारात्मक गुण ने कथा

रेलवे मजिस्ट्रेट ने कोटा से
सवाईमाधोपुर खंड में की चैकिंग

कोटा, (निसं)। ट्रेनों में यात्रा के दौरान चलने वाले बिना टिकट टिकट यात्रियों व अवैध वेण्डरों पर कार्यवाही करने के लिये शुक्रवार को रेलवे के अग्र मुख्य-यायिक मजिस्ट्रेट श्रवण कुमार मीना के नेतृत्व में चौकंग दिवस के दौरान टिकट चौकंग स्टाफ, जीआरपी व आरपीएफ द्वारा कोटा प्लेटफार्म व कोटा से सवाईमाधोपुर के बीच ट्रेनों में औचक निरीक्षण किया गया। रेलवे मजिस्ट्रेट के निर्देशन में टीम द्वारा कोटा से सवाईमाधोपुर के बीच ट्रेन नम्बर 19037 अवध एक्सप्रेस में एवं सवाईमाधोपुर से कोटा के बीच ट्रेन नम्बर 12978 मरुणागर एक्सप्रेस में संयुक्त रूप से चौकंग की गई। चौकंग के दौरान टिकट चौकंग स्टाफ द्वारा जीआरपी व आरपीएफ जाता के सहयोग से चौकंग दौरान बिना टिकट यात्रा कर रहे 16 यात्रियों को पकड़कर रेलवे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किये गए जिनसे मौके पर कुल 20360 रुपये का जुर्माना वसूला गया। वहीं जीआरपी द्वारा प्लेटफार्म व ट्रेनों में गंदगी फैलाने वाले 8 यात्रियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई एवं आरपीएफ द्वारा पुलिस द्वारा रेल अधिनियम के तहत 6 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। रेलवे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किये गये। रेलवे मजिस्ट्रेट ने नेतृत्व में हुई चौकंग के दौरान की गई सम्पत्त कार्यवाही में कुल 43210 रुपये का जुर्माना वसूल कर राशिका कुमर में जमा करवाया गया। उक्त चौकंग में रेलवे कोर्ट स्टाफ हरिओम कुमार बमानात (टीडी) एवं आशुतोष कुमार, जीआरपी के सहायक उपनिरीक्षक अशोक कुमार, कांस्टेबल विकास आहिरवार, आरपीएफ से निरीक्षक सीएस डाबर, सहायक उपनिरीक्षक हरिओम व आरक्षक कुंवरचन्द तथा टिकट चौकंग स्टाफ से सीटीआई विष्णु शर्मा, डिप्टी सीटीआई दिनेश कुमार, डिप्टी सीटीआई नरेन्द्र सिंह चौधरी, टीटीई फतेह सिंह व टीटीई अमन मौजूद रहे।

बिगड़ी बिजली व्यवस्था में सुधार के लिये कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन

ताम्रगंजमंडी, (निसं)। शहर में शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन बिगाड़ि बिजली व्यवस्था को बाध कर लिये धरना, प्रदर्शन करके ऊर्जा मंत्री के नाम जालाना किया। बसरात के बीच भी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अम्बेडकर चौराहे पर धरना देकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एक दर्जन से अधिक वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को सम्बोधित किया। इसके बाद जालाना धरना स्थल से लेती के रूप में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभागे के अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर विद्युत व्यवस्थाओं में सुधार करने की मांगराना किया। शुक्रवार सुबह 10 बजे से अम्बेडकर चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हुआ। धरने में शामिल कार्यकर्ताओं वक्ताओं ने सम्बोधित करके हुये कहा कि वर्तमान केबिनेट मंत्री मदन दिलावर जब विवाचक थे उस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय बिजली की कोई समस्या नहीं थी। इसलिये केबिनेट मंत्री के पद से दिलावर इस्तीफा दें। धरने में ताम्रगंजमंडी, चेचट, मोडक, ढाढादेव, सुकेत, सालाखेडी, जुलुपी व खैराबाद सहित ग्रामीण क्षेत्रों के कांग्रेस कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि एव नैताम्रगंजमंडी वही संघ कांग्रेस के अध्यक्षों, पूर्व पार्षद, जिला परिषद के जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने कार्यकर्ताओं को सम्बोधित किया।

टिकट चैकिंग अभियान चलाया

काटा, (निर्भर) डीआरएम अर्जित कालरा के माधवसिंह में मंडल के वाणिज्य विभाग ने वरतमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के दो माह में कोटा मंडल ने टिकट अभियान चलाकर कुल 60,227 मामलों पकड़े जिससे रेलवे को 4.3 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। कोटा मंडल ने विशेष रूप से लोकल सवारी ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करने वालों पर शिर्का जमा करने हैं। यदि टिकट बिना किसी अभियान में केवल माई माह के आंकड़ों को डाढ़लें तो मंडल ने जौँ के दौरान बिना टिकट, अनुचित टिकट लेकर यात्रा करने वाले एवं बिना बुक नुपे सामान सहित कुल 32,448 मामलों से 2.4 करोड़ रुपये अर्जित किये। जिसमे बिना टिकट के 16,380 मामलों से अनुचित टिकट लेकर यात्रा करने वाले 15986 मामलों एवं बिना बुक नुपे सामान के 82 मामलों पकड़े गए। जौँकि वाणिज्य विभाग के टिकटडट्टर वौँनैँ काँकन कर्मचारी द्वारा कैय नुपे साराहिनौँ कार्य हैं। वरिष्ठ मण्डल वौँनैँ वाणिज्य प्रबन्धनौँ सौँप किये नुपे यात्रिनौँ से अपील कौँ है। टिकट उचित टिकट लेकर ही यात्रा करैँ ताँकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार कौँ असुविधा न हो।

छत्रपाते शिवाजी को किया नमन

काटा, (फिनि) पारंग निगम कोटा उत्तर द्वारा खुबवार को डीसीएम खंड स्थित शिवाजी पार्क में श्रमदान कर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान की प्रतीका शहर संयोजक निवेक राजवंशी के साथियन में श्रमदान कर शिवाजी पार्क को सफाई की गई। इस दौरान उपस्थित जनों ने जल एवं पर्यावरण संयोजक को संकल्प भी लिया। इस अवसर पर निवेक राजवंशी ने कहा कि शिवाजी महाराज देश के महान सपुत थे। उनका शौर्य, पराक्रम और मातृभूमि के प्रति समर्पण अद्वितीय था। उनका कृतित्व हम सब के लिए प्रेरणा है। इस अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान को कोटा शहर सह-संयोजक नरेंद्र लाल प्रजापति, पार्षद गोपाल राम मण्डा, योगेश आहलूवालिया भाजपा एसटी के मोर्चे के प्रदेश महामंत्री अशोक मण्ज, भाजपा जिला कार्यकारी सदन के कौटन सुरेश, जिला कार्यकारी सदन भाजपा, उद्योग नगर भाजपा मंडल महामंत्री हरेन्द्र सिंह, महिला प्रमुख शर्मिला युदुवंशी, कोषाध्यक्ष बलवान सिंह, पूर्व पार्षद कलानाथ निम्पूरे वरेंद्र अध्यक्ष ओम प्रकाश साहू वार्ड अध्यक्ष कैलाश बंद कुमावत, मोशल मीडिया संयोजक रवीन्द्र सुवालका मंडल सदस्य ललित कुमार आदि उपस्थित थे।

गंदगी नालों और सड़कों पर डालने वाले वाहनों पर होगी कार्यवाही

कोटा, (निसं)। नार निगम कोटा उत्तर अब निजी वाहनों के द्वारा मलबा व सेटीक टैंक की गंदगी नालों व सड़कों पर डालने वाला का चालान बनाने व जुर्माने की कार्यवाही को अंजाम देगी। कोटा उत्तर निगम के आयुक्त अशोक त्यागी ने बताया कि इस बारे में सभी स्वास्थ्य निरीक्षकों व कनिष्ठ अभियंताओं को निर्देशित कर दिया गया है कि वो इस संबंध में अपने क्षेत्र में नियमित निगरानी करें और सेटीक टैंक की गंदगी सड़कों व नालियों पर नालों में डालने वालों को मौके पर ही उनका चालान करते हुए न्यूनतम 5 हजार रुपये जुर्माना राशि वसूलें। आयुक्त त्यागी ने बताया कि जानकारी में आया है कि कुछ निजी वाहनों द्वारा निजी तौर पर सड़कों की गंदगी एकत्रित कर नालों व सड़कों पर डाल दी जाती है। जिससे निगम के स्वच्छता के प्रयासों को हानि होती है।

136 सीसीटीवी कैमरे लगाये

काठा, (फिजी) शहर में चले जाये जहाँ सीमांत अपभ्रंशज निगारानी के तहत भाभाशाह व जनसहयोग से शहर में 136 सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं। शहर पुलिस अथीक्षक डॉ.अमृता दुहन ने बताया कि शहर में अपराधिक घटनाओं की रोकथाम एवं अवैध गतिविधियों को निगारानी हेतु शहर पुलिस काठा चले जाये जहाँ अपभ्रंशज निगारानी के तहत शहर के प्रमुख स्थानों का चयन कर कोचिंग एरिया एवं बीडू-भाड़ वाले स्थानों पर भाभाशाह व व्यापारिक प्रतिष्ठानों के सहयोग से 136 सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं।

ऊर्जा मंत्रों ने 8.96 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया

कोटा, (निसं)। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने शुक्रवार को सांगोद में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के पास 33/11 केवी जीएसएस के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। वहाँ पंचायत समिति सांगोद के पास बपावर रोड पर शहरी जल योजना के तहत उच्च जलाशय निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। साथ ही, काशीपुरी मांगलिक धर्मशाला में शिलापट्ट का शिलान्यास और लक्ष्मीपुरा स्थित तालाब पर 101 पौधे रोपने के कार्य का शुभारंभ किया।

ऊर्जा मंत्री ने काशीपुरी मांगलिक धर्मशाला में आयोजित जनसुनवाई में आमजन की समस्याएँ सुनीं और अधिकारियों को मौके ही नितारकर के निर्देश दिए। इस अवसर पर ऊर्जा

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने विकास कार्यों का शिलान्यास किया ।

जलाशय के निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी कर दिया है। पानी स्वच्छ हो, शुद्ध हो, पीने के योग्य हो, इसके लिए फिल्टर प्लांट का क्षमता बढ़ाएंगे। जिसके लिए भी 8 करोड़ रुपए की मंजूरी ले ली गई है।

उन्होंने कहा कि सांगोद में दोनों मुख्य रास्तों को डिवाईड रोड बनाने के लिए 12 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए हैं। नालों का गंदा पानी नदी में जाने

जोसा काउंसलिंग का रिवाइज शेड्यूल जारी

कोटा), (निसं।) आईआईटी-एनआईटी के लिए होने वाली जोसास का कार्सलिंग का रिवाइज शेड्यूल शुक्रवार को जारी किया गया। इस श्रेणिक के अनुसार सम्पूर्ण शेड्यूल प्रोड्युका छत्र राउण्ड में ही संपन्न होगी। पहले राउण्ड की ऑनलाईन रिपोर्टिंग के लिए स्टूडेंट्स को 22 जून शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है। ऑनलाईन रिपोर्टिंग में दस्तावेजों में कमी पा जाने पर स्टूडेंट्स 24 जून शाम 5 बजे तक आई क्रेडीट का रैस्पॉन्स दे सकते हैं। एनआईटी-एनआईटी के करियर डेवेलपमेंट के करियर का कार्सलिंग एक्सपर्ट अमित आहुजा ने बताया कि आईआईटी-एनआईटी, टिपलआईटी व जीएनआईटी-आई मिलकर 127 कॉलेजों को 62,853 सीटों के लिए जोसास द्वारा ऑनलाईन कार्सलिंग चल रही है, जिसमें 23 आईआईटी की 18160 सीटें, 26 एनआईटी की 24525 सीटें, 26 टिपलआईटी की 9940 सीटें एवं 47 जीएनआईटीआई की 10228 सीटें शामिल हैं। जारी किए गए रिवाइज शेड्यूल के अनुसार जोसास कार्सलिंग के दूसरे राउण्ड का सीट आवंटन 25 जून शाम 5 बजे जारी किया जाएगा।

कोटा, (निसं)। शहर को हरा-भरा, स्वच्छ और पर्यावरणीय दृष्टि से समृद्ध बनाने के लिए एक बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान की योजना तैयार की जा रही है। शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में

जिला प्रशासन, नगर निगम (कां) व विकास प्राधिकरण (केपीए) और वन विभाग के अधिकारियों की एक अहम बैठक का बड़ा आयोजित किया गया। इस बैठक पर्यावरणीय संरक्षण, मानसूत सीजन की तैयारी और जन सहभागिता के साथ बड़े स्तर पर हरियाली बढ़ाने के लिए दोस कार्ययोजना पर मंथन हुआ।

बैठक में स्पीकर बिरला ने अधिकारियों को शहर और आसपास के क्षेत्रों में आगामी मानसूत सीजन के दौरान एक पेड़ मां के नाम सीजन के तहत 11 लाख पौधों के रोपण के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पौधारोपण जैसे अभियानों की सफलता सहभागियों समन्वय और सामाजिक सहभागिता पर निर्भर करती है, पौधारोपण

जनआंदोलन का रूप लेगा तभी हम इस सत्य को हासिल कर पाएंगे। सभी विभाज समन्वय के साथ कार्रवाई और कोटावासीयों, स्क्वल, कलेज, सामाजिक संगठनों को भी जोड़ने के निर्देश दिए।

मॉनिटरिंग के लिए तकनीकी का उपयोग हो-बिरला ने कहा कि पौधारोपण केवल औपचारिकता न होकर एक सार्थक और सतत अभियान हो, जिसकी मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित की जाए। पौधों की देखरेख उनकी स्थिति की मॉनिटरिंग के लिए तकनीकी का उपयोग किया जाए। प्रत्येक पौधे का डेटा डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किया जाएगा, ताकि उसकी वृद्धि और स्थिति की समीक्षा की जा सके। उन्होंने कहा कि यदि किसी बड़े चिन्हित क्षेत्र में पौधारोपण किया जाता है, तो वहां टयूबवेल की व्यवस्था कर ड्रिप सिंचाई प्रणाली के माध्यम से पौधों को पानी देने की व्यवस्था की जाए। इससे पौधे सुखेंगे नहीं और उनकी सर्वाइवल रेट भी बढ़ेगी।

औद्योगिक इकाइयों, संस्थाओं को सहभागी बनाए-बिरला ने सुझाव दिया कि औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न इकाइयों के साथ समन्वय स्थापित कर जनसहयोग के माध्यम से पौधारोपण किया जाए और पौधों की सार-संभाल की जिम्मेदारी भी उन्हीं को सौंपी जाए। इस कार्य में स्वयंसेवी संस्थाओं की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाए, ताकि यह अभियान सामाजिक दायित्व और उत्तरदायित्व की भावना से संचालित हो सके।

किसानों को होगा निरुश्रुत्क फलदार पौधों का वितरण-स्पीकर बिरला ने कहा कि शहर के साथ ग्रामीण अंचल में भी हरियाली बढ़े इसके लिए किसानों को निरुश्रुत्क फलदार पौधों वितरित किए जाएंगे, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ उन्हें आर्थिक रूप से भी लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य केवल पौधे लगाना नहीं, बल्कि उन्हें संरक्षित कर कोटा को एक हरित और स्वच्छ शहर बनाना है।

इन्द्रमोहन सिंह
हनी बने
जिलाध्यक्ष

काटा, (सिर्स) भाजपा नेता एडवोकेट इंद्रमोहन सिंह हनी को एडवोकेट सिविल राइड्स सोसाइटी कोटा का नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है। यह जानकारी देते हुए सिविल राइड्स सोसाइटी के प्रदेशध्यक्ष मनमूल सिंह सैनी ने बताया कि एडवोकेट इंद्रमोहन सिंह सामाजिक और धर्म के लगातार उठाते हैं और सक्रिय रहते इसके चलते उन्हें 2 वर्षों के लिए सोसाइटी का कोटा का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। मोशन प्रोजेक्शन नीट अंडीज में 11 साल पूरे होने पर खास अंदाज में मनाया जश्न किया।

सत्यनारायण मेघवाल एडवोकेट

मैंने अपना पुराना नाम पल्लवी कोहली चन्डोक से बदलकर नया नाम पल्लवी कोहली रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम कल्याणी त्रिवेदी से बदलकर नया नाम कल्याणी कुनाल सोनी रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

पता-कल्याणी कुनाल सोनी पत्नी कुनाल सोनी 804 महावीर नगर-2 कोटा

नालों को करवाया साफ

काटा, (फिरोज़) तेज बारिश के कारण शुक्रवार को अवलूह ग्रेड स्टेशन क्षेत्र के राम मंदिर वाली बड़ू नाले को क्षेत्र उत्तर नगर निगम के प्रतिपक्ष के नेता लव शर्मा द्वारा गैम के पर खड़े रहकर तत्काल साफ़ करवाया गया और नाले में फंसे अवरोधों को जेसीबी मशीन व सफाई श्रमिकों के जरिए हटवाया। जिससे नाले का बहाव सुगम हो गया। निगम उत्तर प्रतिपक्ष के नेता लव शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को राजधानी के जमानकारी मिली कि राम मंदिर का बड़ा नाला बारिश के कारण बहकर आकर कचरे से अवलूह हो गया है। जिससे नाले का पानी आवागमन के मार्ग पर फैलने व यातायात बाधित होने की आशंका बन गई है। उन्होंने बताया कि वो तत्काल मौके पर पहुंचे और एक जेसीबी मशीन व सफाई श्रमिकों को बुलाकर तत्काल नाले के अवरोधों को हटवाया। जिससे नाले का पानी पुनः सुगमता के साथ प्रवाहित होने लगा। नाला सफाई की कार्यवाही के दौरान स्वास्थ्य अधिकारी मोती लाल चौधरी, स्वास्थ्य निरीक्षक दीपक सोनवाल तथा समाजसेवी जतिन अंगनानी भी मौके पर मौजूद रहे।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केटीए)
 क्रमांक: LU2012/KOT/2025-26/101011 **नोटिफिकेशन** दि. 20.06.2025
श्री PANKAJ VIJAY पुत्र श्री RANESH CHANDRA VIJAY जाति MAHAJAN निवासी E-2
GOPAL VIHARI, POLICE LINE KOTA श्री ANKUR VIJAY पुत्र श्री RANESH CHANDRA
VIJAY जाति MAHAJAN निवासी E-2 GOPAL VIHARI, POLICE LINE KOTA ने इस
 कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **पर्यवेक्षण** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने
 अधिकारि अधिकारी के नियंत्रण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्: -

[illegible]

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक-एफ-15/क.पूर./2025/539 विज्ञापित दिनांक-20.6.25

सर्व साधारण कोटों के विज्ञापित सूचित किया जाता है कि ग्राम बालाकुंड में स्थित कृषि भूमि यानामा नु. जवाहर नगर भूखंड संख्या डी-98 खसरा नं. 91/40 आवेदक/आवेदिका श्री लखवी सिंह सिंह पुत्र नरु. श्री कपाल सिंह निवासी डी-100, जवाहर नगर, कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन नमक हस्तांतरण हेतु श्रीकपाल कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखंड का पट्टा क्रमांक 117 प्लॉट नं. 21.05.2001 को श्री कपाल सिंह पुत्र नरु. पुत्री दिलीप सिंह के पक्ष में प्रतीक किया गया था। पट्टादारी को मनुष्य माना पर अनुसूचित दिनांक 30.05.2019 को हो चुकी है। मृतक कपाल सिंह पुत्र के स्थिक्त बालिष्ठान पति अमरजीत कौर, पुत्री हरिद्वन्द को, मंजीत कौर, पुत्र सुखवीर सिंह, लखवी सिंह है। बालिष्ठान द्वारा जय सिंह, हकन्या पुत्र दिनांक 09.08.2019 को अमरजीत कौर, हरविन्द कौर, मंजीत कौर, सुखवीर सिंह द्वारा आवेदक पक्ष में किया गया है।

अतः श्री लखवी सिंह पुत्र नरु. श्री कपाल सिंह के पक्ष में नम हस्तांतरण जारी किया जाने में यह किस्ती व्यक्ति को कौन आपत्ति हो तो अन्तर 7 वर्ष कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में ओरोहस्ताक्षरकारी को प्रस्तुत करें। मिमडर पुत्र गुप्ते के बाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपस्थित कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा



भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

STATE BANK OF INDIA
GARH PALACE JHALAWAR - 31268

To,
M/s Galaxy Stone Industries
Prop. Mr. Arshil Sheik
G-30A, RICCO Industrial Area, Phase III, Jhalawar, Distt. Jhalawar (Raj.)- 326001

Dear Sir,

NOTICE U/S 13(4) OF SECURITISATION & RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS & ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 WITHDRAWAL

With reference to the captioned subject, please note that without prejudice to the Bank's rights & contentions, possession notice U/S 13(4) issued by Bank under SARFAESI ACT 2002 is hereby withdrawn and possession is restored of the property mentioned here under :-

This is without Prejudice to Bank's right and contentions to initiate / proceed further with legal action under SARFAESI Act 2002 for recovery of the Bank Dues.

Details of Property :-

Plot No. G 30 A, RICCO Industrial Area Phase III, Jhalawar, Distt. Jhalawar (Raj.) - 326001	Total Area : 1196 Sq.Mtr.
--	----------------------------------

Bounded in the :-

North By : RICCO Plot No. G-30 (B) East By : RICCO Road 18 Mt. Wide	South By : RICCO Plot No. G-30 West By : RICCO Land
--	--

Authorised Officer
State Bank of India

कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा, जिला- चित्तौड़गढ़ (राज.)				
क्रमांक/न्याया/पूषि/2025-26/883	सार्वजनिक आपत्ति सूचना			दिनांक-20.6.25
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/भूखंडधारी श्री संदीप सिंह पिता श्री रंजित सिंह एवं श्री विजेन्द्र ल्यागी पिता श्री अजुन सिंह ल्यागी निवासी रावतभाटा के द्वारा नया बाजार अर्थात् योगेना के भूखंड संख्या 270 साईज 40x50 फीट क्षेत्रफल 2000 का वीरगुप्ता विक्रय प्र दिनांक 18.01.2010 को उक्त भूखंड के उपविभाजन प्लान अनुसार दो भागों में निम्नानुसार विभाजित कर उपविभाजन का अनुमोदन चाहा गया है।				
विभाजित भाग	उपविभाजित भूखंड सं.	व्यामिश्र	साईज व क्षेत्रफल	चतुर्थ पट्टीस को स्थिति
प्रथम	270-ए	श्री संदीप सिंह पिता श्री रंजित सिंह निवासी रावतभाटा	20x50 =1000 वर्गफीट	पूर्व में-प्लान नं. 269 परिचय में-उपविभाजित भूखंड संख्या 270-बी (जो विजेन्द्र ल्यागी ने क्रय किया है) उत्तर में-रोड नया बाजार 20'6" दक्षिण में-रोड नया बाजार 20'6"
द्वितीय	270-बी	श्री विजेन्द्र ल्यागी पिता श्री अजुन सिंह ल्यागी निवासी रावतभाटा	20x50 =1000 वर्गफीट	पूर्व में-उपविभाजित भूखंड संख्या 270-ए (जो श्री संदीप सिंह ने क्रय किया है) परिचय में-प्लान नं. 271 उत्तर में-रोड नया बाजार 20'6" दक्षिण में-रोड नया बाजार 20'6"

कार्यालय नगर निगम कोटा उत्तर (राज.)

यथावत उपबंधित २०१० के अनुसार आरजुनदेव पुत्र आ खजुनदेव निवास २-२८-१५/१६ आकाश नगर केनाल मार्ग बोखड़ा कोटा में आटा-चक्की लगाने की अनुमति चाही गई है।

इस संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को किसी भी प्रकार की कोई अप्रति हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन दिनांक से ०७ दिसर की अवधि में राजीव गांधी भवन नगर निगम कोटा उतर के ब्याक सी के द्वितीय तल के कमरा नं. ३०७ में अपनी आप्रति प्रस्तुत करें। अन्यथा उपरोक्त उपबंधित के अनुसार कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जायेगी। सूचित हो।

उपायुक्त नगर निगम कोटा (उत्तर)

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांक:-न/पंकट/द,जोन-प्राथम/प/मि.उप/2025/3982 दिनांक: 20.6.25

स्थानित हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञापित

सर्व सहायक को को सूचित किया जाता है कि श्रीमती उर्मिला जैन पत्नी श्री गोपाल लाल जैन निवासी-86 प्रताप नगर दादाबाही (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण भूखंड संख्या-87 प्रताप नगर दादाबाही कोटा (राज.) नगर निगम कोटा नगर हस्तारण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। भूखंड संख्या-87 प्रताप नगर दादाबाही कोटा शेफरल-980 वर्गफुट का कार्यालय नगर विकास यान स कोटा द्वारा प्राप्त क्रमांक-रिकवरी/1984-85/2112 दिनांक 28.03.1985 को श्रीमती कमला याई पत्नी श्री फूलचन्द को नगरीय निगम किया गया। श्रीमती कमला याई पत्नी श्री फूलचन्द ने उपर भूखंड को स्थलिय वसोपयोगी बना दिया 09.09.1998 से नगर निमती उर्मिला जैन पत्नी श्री गोपाल लाल जैन के पक्ष में की गई है। श्रीमती कमला याई पत्नी श्री फूलचन्द को मृत्यु दिनांक 19.11.2006 को हो चुकी है। उनकी मृत्यु उपरांत पुत्र विधिव कार्यास श्रीमती उर्मिला जैन पत्नी श्री गोपाल लाल जैन है। श्रीमती उर्मिला जैन पत्नी श्री गोपाल लाल जैन के पक्ष में नगर हस्तारण को कार्यवाही को जानी है।

आवक के द्वारा प्रस्तुत आवदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम कोटा हास्तान्तरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध स्थापित है, कोई आपत्ति हो तो विज्ञापित जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

कार्यालय नगर निगम, कोटा-दक्षिण, कोटा, राजस्थान
 क्रमांक:-नगिनको/उपायुक्त प्रथम/प.नि.अनु./2025/39996 दिनांक:- 20.6.25

स्वामित्व हस्तान्तरण बाबत सार्वजनिक विज्ञापित

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती नमिता नागपाल पुत्री श्री मुल्करना नागपाल निवासी 247 शोचिंग सेक्टर कोटा द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर पृथक संख्या 247 शोचिंग सेक्टर कोटा क्षेत्रफल 2400 वर्गफुट का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने का आवेदन किया है। पृथक संख्या 247 शोचिंग सेक्टर कोटा क्षेत्रफल 2400 वर्गफुट को राजस्व सकारा द्वारा डीड औफ़ दचार्ज मण्डी कोटवाली चम्बल पोल्डर कोटा द्वारा दिनांक 06.09.1961 को श्री राम तुलाराम पुत्री श्री रामलाल के पक्ष में जारी की गई है। आवेदन कोटा प्रस्तुत शोधन पर के अनुसार श्री राम तुलाराम कोटी मुल्य वर्ष 1965 में हो चुकी है एवं मुल्य प्रमाण पर के अनुसार उत्पत्ति प्रती श्रीमती रामधायी पुत्री श्री राम तुलाराम कोटी मुल्य दिनांक 07.02.1988 को हो जो जाने के उपरत आवेदिका श्रीमती रामधायी पुत्री श्रीमती कुमारी पुत्री श्री मुल्करना नागपाल द्वारा शिषिक वासिस्त घोषणा शोधन पर के आधार पर नागपालर चाहा गया है। उक्त पृथक संख्या 247 शोचिंग सेक्टर कोटा क्षेत्रफल द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण उक्त पृथक के स्वामित्व नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही का ज रही है।

उक्त पृथक का स्वामित्व नाम हस्तान्तरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी की भी उक्त पृथक से संबंध रहता है, को कोई आपत्ति हो तो विवाजि जारी होरे के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त द्वितीय कक्ष में प्रस्तुत करे ताक मियार आपत्ति मान्य नहीं होना।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

चंबल नदी के राजस्थान में बने बांध लबालब, कोटा बैराज से लगातार पानी की निकासी संभव

कैचमेंट एरिया में होने वाली बारिश से लगातार पानी की आवक होने पर निकासी की जाएगी

कोटा, (नि.सं)। चंबल नदी के राजस्थान में बने तीनों बांध में इस बार लबालब पानी है। ऐसे में इनका कैचमेंट एरिया में होने वाली बारिश से लगातार पानी की आवक होने पर निकासी की जाएगी। इसी के चलते

■ कोटा बैराज से दो गेट खोलकर 6500 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है, जिसमें एक गेट 3 फीट और दूसरा 5 फीट खोला गया है

राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध से मशीन डिस्चार्ज किया जा रहा है। बिजली उत्पादन भी शुरू हो गया है। साथ ही कोटा बैराज से गेट डिस्चार्ज भी शुरू कर दिया गया है। इन तीनों डैम के गेट खुलेंगे तो पानी का डिस्चार्ज किया जाएगा। इसके बाद चंबल नदी कोटा से लेकर धौलपुर तक अलर्ट मोड पर रहेगी। इस बार यह तीनों डैम 96.69 फीसदी फुल हैं। इन तीनों की पूरी कैपेसिटी 3084.03 मिलियन क्यूबिक मीटर है, जबकि इनमें वर्तमान में पानी 2982.23 मिलियन क्यूबिक मीटर है।

राणा प्रताप सागर बांध के सहायक अभियंता हरीश तिवाड़ी का



कोटा बैराज से दो गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है।

कहना है कि मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित चंबल नदी के सबसे बड़े बांध गांधी सागर बांध का लेवल कम किया गया था। इसके चलते वहां से पानी डिस्चार्ज गर्मी के सीजन में हुआ था। राणा प्रताप सागर बांध उस समय खाली था। ऐसे में राणा प्रताप सागर बांध से पानी छोड़ने की जगह उसे स्टोर कर लिया गया। राणा प्रताप सागर बांध का लेवल बढ़ गया है। साल 2024 में 20 जून के दिन वहां पर फुल कैपेसिटी 2904.85 की एवज

है कि जून महीने में ही डैम से पानी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जबकि मशीन डिस्चार्ज शुरू हो गया है। सहायक अभियंता हरीश तिवाड़ी के मुताबिक राणा प्रताप सागर बांध में ज्यादातर पानी की आवक गांधी सागर बांध के पानी छोड़ने से होती है। इस बार गांधी सागर बांध बीते साल की अपेक्षा इस बार ज्यादा खाली है। बीते साल वहां कैपेसिटी 7164.94 एमसीएम की तुलना में 58 फीसदी यानी 4173.85 एमसीएम पानी था

इस बार यह पानी महज 46.87 फीसदी यानी 3358.25 है। ऐसे में गांधी सागर बांध को भरने में काफी ज्यादा समय लगेगा लेकिन आरपीएस डैम के कैचमेंट एरिया में होने वाली बारिश के पानी को तुरंत निकालना पड़ेगा। जवाहर सागर बांध के केसमेंट एरिया में ब्राह्मणी नदी का भी पानी आता है। यह शुरूआत में हजारों क्यूसेक होता है और बाद में बढ़कर लाख क्यूसेक ऊपर भी चला जाता है। ऐसे में लगातार निकासी भी होगी।

कोटा बैराज की कुल क्षमता 112 मिलियन क्यूबिक मीटर के आसपास ही है। जबकि जवाहर सागर डैम की क्षमता 67.12 एमसीएम है। जबकि राणा प्रताप सागर बांध इन दोनों डैम की क्षमता से 16 गुना ज्यादा बड़ा है। ऐसे में राणा प्रताप सागर बांध से पानी की निकासी होने पर इन दोनों डैम से तत्काल निकासी की जाती है क्योंकि इनमें पानी को स्टोर ज्यादा नहीं किया जा सकता है।

कोटा बैराज से छोड़ा पानी : सहायक अभियंता निकिता पारेता ने बताया कि बारिश के सीजन को देखते हुए फ्लड सेल जल संसाधन विभाग ने चालू कर दी है। इसके जरिए हर चंटे डैम और उनके पानी की आवक व डिस्चार्ज की रिपोर्ट ली जा रही है। इसे 24 घंटे जिला कलेक्टर और जंयपुर मुख्यालय को अपडेट भी कराया जाता है ताकि पानी डिस्चार्ज होने पर नीचे अलर्ट जारी हो सके। राणा प्रताप सागर बांध में 12167 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है। मशीन के जरिए 1790 क्यूसेक डिस्चार्ज किया जा रहा है। जबकि जवाहर सागर बांध से 3800 क्यूसेक पानी आ रहा है जिसमें ब्राह्मणी नदी का पानी भी है। यहां से मशीन डिस्चार्ज किया जा रहा है। इसी तरह से कोटा बैराज से दो गेट खोलकर 6500 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। जिसमें एक गेट 3 फीट और दूसरा 5 फीट खोला गया है।

टेम्पो ट्रक से 1183 किलो घी व वेज फेट जब्त

पाली, (नि.सं.)। जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुये आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि नियंत्रण एच गुड्टे के दिशा निर्देश पर पाली जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विकास मारवाल व खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में मिलावटी घी की सूचना पर देर रात को दबिश देकर नेशनल हाइवे-14 पर जाउन के समीप टेम्पो ट्रक से 1183 किलो घी व वेज फेट जब्त किया गया।

सीएमएचओ डॉ. विकास मारवाल ने बताया कि मुखबोर की सूचना पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मय दल द्वारा तेज गती से चल रहे टेम्पो ट्रक का पीछा कर उसे जाउन पेडोल पम्प पर रूकवाया गया, जिसकी जांच करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चन्द्र शर्मा को बिना बिल के विक्रय होने जा रहे घी का मिलावटी होने का संदेह हुआ जिस पर विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र जाइन पर टेम्पो ट्रक में भर माल को खाली करवाया गया।एफएसओ द्वारा टेम्पो ट्रक

- पाली जिले के विभिन्न गांवों में दुकान व प्रतिष्ठानों पर विक्रय हेतु जा रहा था घी
- खाद्य सुरक्षा अधिकारी मय दल द्वारा तेज बारिश के बावजूद देर रात 12 बजे तक कार्रवाई की

के चालक शक्ति सिंह रावत से पृष्ठतात करने पर बताया कि श्री श्याम फुड प्रोडेक्ट अजमेर के निर्माण एवं उत्पादक इकाई से घी व वेज फेट टेम्पो ट्रक में भरवाया गया, जो पाली जिले के विभिन्न गावों में दुकान व प्रतिष्ठानों पर विक्रय हेतु जा रहा था। मामले को गम्भीरता से लेते हुये खाद्य सुरक्षा अधिकारी व सीएमएचओ ने जप्त सभी खाद्य पदार्थ को सीज कर उनके सेम्पल लिये। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल के साथ फूड सैफ्टी टेक्निशियन खुशाल चन्द सैन, ऑर्परेटर ओम प्रकाश प्रजावत, लक्ष्मणदान चारण उपस्थित रहे।

डॉ. विकास मारवाल ने बताया कि राज्य सरकार के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मिलावट के रोकथाम पर कार्रवाई करते हुये टेम्पो ट्रक से 6 ब्रांड के घी व वेज फेट जप्त

किये।इनमे घी ब्रांड सरल, नमस्ते कृष्ण, श्री राजवंशी सुपर सारथी घी, सरल के 15 किलो टोन व वेज फेट डेयरी सरस रिफायंड पॉम ऑयल सारस कुंकीण मीडियम ऑयल सहित आधा लीटर एक लीटर व पांच लीटर घी की सामग्री को सीज किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चन्द्र शर्मा ने बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधीकरण द्वारा बनाये गये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 कानून के तहत खाद्य पदार्थों में मिलावट का संदेह होने होने पर अजमेर के सराधना स्थित श्री श्याम फूड प्रोडेक्स निर्माण एवं उत्पादक इकाई द्वारा बाजार में विक्रय के लिए जाने वाले घी पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मय दल द्वारा तेज बारिश के बावजूद देर रात 12 बजे तक कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर आने वाले यात्रियों के लिए शुक्रवार की सुबह निराशाजनक रही, जब एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या एआई 645 को तकनीकी समस्या के चलते रद्द करना पड़ा। यह फ्लाइट मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सुबह 9.15 बजे उड़ान भरने वाली थी और इसे जोधपुर में सुबह 11.05 बजे लैंड करना था लेकिन उड़ान से कुछ देर पहले ही एयरलाइंस को विमान में तकनीकी खराबी की सूचना मिली। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एयर इंडिया प्रबंधन ने तत्काल उड़ान रद्द करने का निर्णय लिया।

इस फैसले के बाद यात्रियों को खासी फेरशाली का सामना करना पड़ा। खासकर उन्हें जिनको जरूरी कार्यों के लिए यात्रा करनी थी। फ्लाइट के रद्द होने

- यात्रियों ने एयर इंडिया की ओर से समुचित जानकारी और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं मिलने की शिकायत एयरपोर्ट प्रशासन और एयर इंडिया अधिकारी से की, रिफंड जल्द उपलब्ध कराने की मांग की, यात्रियों ने नाराजगी जताई

की जानकारी यात्रियों को अंतिम समय में मोबाइल मैसेज के माध्यम से दी गई, जिससे कई यात्री असमंजस की स्थिति में आ गए। कुछ यात्री पहले से एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, जिनमें वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। उन्हें वैकल्पिक उड़ान की तलाश करनी पड़ी या फिर अन्य माध्यमों से यात्रा के लिए रवाना हुए।

यात्रियों ने एयर इंडिया की ओर से समुचित जानकारी और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं मिलने की शिकायत

एयरपोर्ट प्रशासन और एयर इंडिया अधिकारी से की। यात्रियों ने एयर इंडिया से वैकल्पिक उड़ान की सुविधा या पूरा रिफंड जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की मांग की है। कई यात्रियों का कहना है कि उन्हें न तो काउंटर पर सही जानकारी मिल पाई और न ही हेल्पलाइन से कोई संतोषजनक जवाब मिला। कुछ यात्रियों ने सोशल मीडिया पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की और एयरलाइन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

**ENGINEERING COLLEGE BHARATPUR HOSTEL**
(A Constituent College of Rajasthan Technical University, Kota)
Village-Shyorana, Near Sewar & National Highway-11, Bharatpur
क्रमांक : GECBH/HOSTEL/2025-26/11 दिनांक : 19.06.2025

निविदा आमंत्रण सूचना
अभियांत्रिकी महाविद्यालय भरतपुर के छात्रवासों में मंस संचालन मय खाद्य सामग्री हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है जिसकी विस्तृत जानकारी के लिए महाविद्यालय की वेबसाइट www.ecbharatpur.ac.in एवं कार्यालय पर महाविद्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
-प्राचार्य

**महाराजा प्रताप कुषि एवं प्रोद्योगिकी विविधविभाग, उदयपुर (राज.)**
क्रमांक- वीएससी/राजी/साप्ताहिक/निविदा-01/2025-26/6095 दिनांक: 20.06.2025

ई- निविदा सूचना- 01 (2025-26)
माननीय कुलपति महोदय, म.प्र.कु.प्रौ.वि.वि. उदयपुर की ओर से कलर प्रिन्टिंग कार्य कर रहे हेतु (अनुमानित लागत रु. 20 लाख), मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। समस्त शर्तें एवं विस्त्व विवरण www.eproc.raajasthan.gov.in, www.sppp.raajasthan.gov.in व www.mpuat.ac.in पर देखा जा सकता है।
UBN NO- ATU2526SLRC00109 निरेशक, आयोजना एवं परिवेक्षण निरेशालय

Office of the Superintendent Engineering and Project Manager WCDC, Karauli
No. 742 Date: 13-06-2025

NOTICE INVITING BID
NIB No 14/2025-26
Bids for Gabian stracture work Project PMKSY2.0 Block - Mandrail of estimated value INR 224.17 Lacs [01 Package] are invited from interested bidders up to 06.00 PM, 23-06-2025. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (<https://eproc.raajasthan.gov.in>) of the state, departmental website.
NIB CODE:- WSC2526A0304
UBN NO- WSC2526WSRC00504

Superintending Engineer and Project Manger
WCDC Zila Parishad Karauli

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता एवं परियोजना प्रबंधक वाटरशेड सेल कम डाटा सेंटर जिला परिषद जालौर
क्रमांक-एच/निविदा/2025-26/628 दिनांक-11.06.2025

NOTICE INVITING BID NIT NO 05/2025-26
Bids for NRM Works Under PMKSY 2.0 project area in Ahore of estimated Value INR 27.99 Lacs are invited from interested bidders up to 3.00 PM 24-06-2025. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (<https://eproc.raajasthan.gov.in> or <https://Sppp.raajasthan.gov.in>) of the state.

NIT NO.	Work Name & Block	NIB NO.	UBN NO.
NIT-05/2025-26	Open Air Gym, Time shed & Stage in play Ground and balvatika (Ahore)	WSC2526 A0287	WSC2526 WSR00483

(Laxman Singh Sandu) SE & PMWCDC, ZILA PARISHAD JALORE
DDO CODE NO. 28606

DIPR/C/8207/2025

Office of the Superintendent Engineering and Project Manager WCDC, Karauli
No. 739 Date: 12-06-2025

NOTICE INVITING BID
NIB No 13/2025-26
Bids for Talab, talai, Periferal band work Project PMKSY2.0 Block - Mandrail of estimated value INR 68.50 Lacs [01 Package] are invited from interested bidders up to 06.00 PM, 22-06-2025. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (<https://eproc.raajasthan.gov.in> or <https://Sppp.raajasthan.gov.in>) of the state, departmental website.
NIB CODE:- WSC 2526 A0294
UBN NO- WSC, 2526 WSR00491

Superintending Engineer and Project Manger
WCDC Zila Parishad Karauli

बीकानेर, (नि.सं)। प्रदेश के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में ऑनलाइन आवेदन के बाद अभ्यर्थियों को सीटों का आवंटन हो गया है। पिछले साल 25 अगस्त को हुई परीक्षा में शिक्षकों को अभी तक इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पोस्टिंग नहीं मिली है। पदस्थान में विलंब से शिक्षकों में नाराजगी है।

आक्रोशित शिक्षकों माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षक संघ एलिमेंट्री सेकेंडरी

- आक्रोशित शिक्षकों माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में विरोध प्रदर्शन किया

टीचर एसोसिएशन (रेसटा) के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावत के नेतृत्व में शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के मुख्य प्रशासनिक भवन पर प्रदर्शन करके स्टाफ ऑफिसर डॉ. अशोक

जोधपुर में डॉक्टर्स का पूर्ण कार्य बहिष्कार

जोधपुर, (कासं)। डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज के फार्मसी विभाग के रेजिडेंट डॉ. राकेश विश्नोंई के 13 जून को सेल्फाश खाकर आत्महत्या किए जाने का मामला सातवें दिन शुक्रवार को भी नहीं सुलझ पाया। जयपुर के एसएमएस अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन जारी है। रेजिडेंट डॉक्टरों ने डॉक्टर्स ने पूर्ण कार्य का बहिष्कार आज से कर दिया। मामले में अभी तक डॉ. एसएन. मेडिकल कॉलेज प्रशासन और सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने से जोधपुर में रेजिडेंट डाक्टर भी हड़ताल पर उतर गए हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसियेशन के अध्यक्ष हीरालाल और महासचिव रंजीत चौधरी आपात स्थिति में सेवासं दे रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर डॉ. राकेश विश्नोंई के आत्महत्या प्रकरण में न्याय की मांग को लेकर जोधपुर रेजिडेंट डाक्टर्स एसोसियेशन जोधपुर से जुड़े करीब पांच छह से डॉक्टर्स हड़ताल पर उतर गए हैं।

सूरतगढ़, (नि.सं)। उपखंड की ग्राम पंचायत मोकलसर के सरपंच गणेशराम गोदारा को प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि स्वीकृत करने के बदले रिश्तत मांगने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई राजस्थान पंचायतयतारा अधिनियम 1994 की धारा 38(4) के तहत की गई है। निलंबन आदेश अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव इन्द्रजीत सिंह ने जारी किया।

मामले की शिकायत मोकलसर के वार्ड नंबर पांच के निवासी गणेशराम कुम्हार ने दर्ज करवाई थी। शिकायत में कहा गया था कि सरपंच गणेशराम गोदारा ने उनके पिता गोविंदराम कुम्हार से प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति के लिए 12,000 की रिश्तत मांगी थी। शिकायत के अनुसार 24 मई 2025 को सरपंच ने 10,000 नकद ले लिए थे।

- एबीसी ने 10 हजार की रिश्तत लेते ट्रैप किया था
- निलंबन अवधि के दौरान किसी भी पंचायत कार्य या कार्रवाई में भाग नहीं ले सकेगा सरपंच

इस मामले को एसीबी ने गंभीरता से लिया और सरपंच को कर्तव्यों में लापरवाही और अपकीर्तिकर आचरण का दोषी पाया। जिसके बाद उसे रीा हाथ ट्रैप करने के लिए जाल बिछाया गया और कार्रवाई को अंजाम देते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। निलंबन के बाद सरपंच को आरोप पत्र जारी किया गया है और वे निलंबन अवधि के दौरान किसी भी पंचायत कार्य या

कार्रवाई में भाग नहीं ले सकेंगे।

एसीबी के हनुमानगढ़ और बीकानेर की टीमों ने 24 मई को बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए सूरतगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मोकलसर के सरपंच गणेशराम गोदारा को 10,000 रुपए रिश्तत लेते पुराना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित आवास से रीा हाथों गिरफ्तार किया था।

एसीबी के महानिदेशक के मुताबिक एबीसी हनुमानगढ़ चौकी को शिकायत मिली थी कि मोकलसर सरपंच गणेशराम गोदारा पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारी के पिता के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि स्वीकृत करवाने के बदले 12,000 रुपए रिश्तत मांग रहा था। शिकायत की सत्यता जांचने के बाद एसीबी ने जाल बिछाया और सरपंच गणेशराम को 10,000 रुपए रिश्तत लेते मौके पर गिरफ्तार किया था।

सरकारी कर्मचारी का संदिग्ध हालत में शव मिला

■ प्रथमदृष्टया आशंका जताई जा रही है कि किसी विषाक्त पदार्थ का सेवन किया हो

■ मौत के सही कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा, पुलिस ने जांच शुरू की

भीलवाड़ा, (नि.सं)। जिले के मांडल थाना क्षेत्र में बीती शाम एक सरकारी कर्मचारी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे पेड़ के नीचे मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 49 वर्षीय विष्णु पारीक पुत्र सत्यनारायण पारीक, निवासी रायपुर के रूप में हुई है। वे वर्तमान में भीलवाड़ा में राजकीय सेवा में कार्यरत थे। सूत्रों के अनुसार, गुरुवार सुबह विष्णु पारीक अपनी स्कूटी लेकर कार्यालय के लिए निकले थे, लेकिन देर शाम तक जब वे घर नहीं लौटे, तो परिजन चिंतित हो उठे। इसी दौरान हरिपुरा-भगवानपुरा मार्ग पर राहगीरों की नजर सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे अचेत अवस्था में पड़े व्यक्ति पर पड़ी। उन्होंने तुरंत मांडल उपजिला चिकित्सालय में सूचना दी, जहां विष्णु पारीक को लाया गया। डॉक्टरों ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मांडल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। परिजनों की भी सूचना दी गई, जो मौके पर पहुंच गए। मृतक के चेहरे पर विशेष रूप से आंखों के नीचे नीले निशान और मुंह से खून निकलने के लक्षण देखे गए हैं, जिससे प्रथमदृष्टया आशंका जताई जा रही है कि विष्णु पारीक ने किसी विषाक्त पदार्थ का सेवन किया हो। हालांकि, मौत के सही कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं, इस घटना से

इलाके में शोक और भय का माहौल है। लोगों में इस बात को लेकर चर्चाएं हैं कि आखिर विष्णु पारीक की मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई। परिजन भी स्तब्ध हैं और उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है।

मांडल थाना प्रभारी विक्रम सिंह शेरावत ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि घटना से जुड़े कोई सुराग मिल सके। राजकीय कर्मचारी विष्णु पारीक को अचानक हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस मामले को हर एंगल से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि यह मामला आत्महत्या का है, दुर्घटना का या किसी साजिश का। उनकी मौत से परिवार और समाज में शोक की लहर है।

कार्यालय नगरपरिषद, जालौर (राजस्थान)
क्रमांक : नगपन/स्टोर / 2025 / ई-निविदा / 1794 दिनांक :- 12.06.2025

:: ई-निविदा सूचना सं. 02/2025-26 ::

नगरपरिषद, जालौर क्षेत्र में Maintenance Of Led Street Lights And Road Light Lines In Municipal Coucil (Uib) Area (Including Material & Amp Manpower/Labour) कार्य के लिए मात एंव सेवाओं के उपापन के लिए दर संविदा वित्तीय वर्ष 2025-26 (31.03.2026) के लिए कार्य दर (रेट कोन्ट्रैक्ट) हेतु विभिन्न फर्मों, ठेकेदारों, अधिकृत डिलरों से एतद्वारा मोहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है-
NIB CODE :-DLB2526A2387 आयुक्त नगर प.रिषद, जालौर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-चित्तौड़गढ़
क्रमांक-टी.एस./2025-26/ई-632 दिनांक-07.06.2025

NOTICE INVITING BID - 11/2025-26
Bids for Construction of Atal Pragati Path Satpura Road to Retuliya Chowk (Ghosunda) in Division Chittorgarh Procurement are invited from interested Bidders upto 6.00 PM of 23.06.2025 Other particulars of the Bid may be visited on the Procurement Portal (<http://sppp.raajasthan.gov.in>) of the state website. The approximate value of the Procurement in Rs. 15797033.00
NIB CODE-PWD2526A1182
UBN NO.-PWD2526WSOB04031
DIPR/C/7858/2025 Executive Engineer PWD Dn. Chittorgarh

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड मालपुरा
क्रमांक : 420 दिनांक : 9-6-2025

निविदा सूचना संख्या: 08/2025-26 खण्ड मालपुरा
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से खण्ड मालपुरा में सड़क भवन निर्माण हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान एवं राज्य सरकार के अन्य विभागों तथा केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवं दूर संचार विभाग / रेल्वे इत्यादि में पोजीटिव सेलेक्शन, जो कि उद्देश्यजनक सरकार के "ए" एवं "एच" , "बी" , "सी" , "डी" श्रेणी के सेलेक्शन के संदर्भ में, से करणी हेतु ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा प्रपत्र में प्राप्त की जायेगी। निविदा के सफल विजेता वेबसाइट www.dipronline.org व www.eproc.raajasthan.gov.in एवं www.sppp.raajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

NIB code	PWD2526A1187	6	PWD2526WSRC04064
1	PWD2526WLB0B04051	7	PWD2526WSRC04065
2	PWD2526WSWOB04053	8	PWD2526WSRC04066
3	PWD2526WSWOB04057	9	PWD2526WSRC04067
4	PWD2526WSRC04062	10	PWD2526WSRC04068
5	PWD2526WSRC04063	11	PWD2526WSRC04069

DIPR/C/7797/2025 अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड यात्रियों

राजस्थान सरकार
कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर
क्रमांक-F.32(B) (Model Shop)XL/2025-26-05066/170 दिनांक: 18.06.2025

मॉडल शॉप्स (Model Shops) के अनुनाप्र हेतु ई-नीलामी आमंत्रण सूचना-
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक ए.4 (1) वि/रा/आ/2025 दिनांक 29 जनवरी, 2025 के द्वारा जारी आबकारी एवं मय-रचना नीति वर्ष 2025-29 के प्रावधानानुसार मॉडल शॉप्स की ऑनलाईन ई-नीलामी के लिये विभागीय वेबसाइट <https://iems.raajasthan.gov.in> पर निम्नानुसार ई-बोली आमंत्रित की जाती है:-

क्र.सं.	नीलामी की दिनांक	नीलामी का समय
1	07-07-2025	प्रातः 11.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक

- ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता द्वारा विभागीय वेबसाइट <https://iems.raajasthan.gov.in> से अपने के माध्यम से लॉगइन करते हुए विभागिय ई-ऑक्शन पोर्टल में निर्धारित प्रक्रियानुसार दिनांक 10.06.2025 (21.00 बजे से एक घण्टी पोजीकरण करने उपरान्त ऑनलाइन नीलामी में भाग लिया जा सकेगा। इच्छुक बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व संबंधय राजस्थान सरकार के पोर्टल <https://sso.raajasthan.gov.in> पर "Citizen" केटेगरी के अन्तर्गत SSOD नकलाना होगा।
- नीलामी एक कार्य दिनांक में न्यूनतम पांच घण्टे की होगी एवं उसके पश्चात् जब तक बोली लागू रहे तब तक 10 मिनट के अन्तत विस्तार (indefinite extension) में बढ़ाकर ली जा रहीेगी।
- बोलीदाता को कम से कम रु. 10,000/- (अथवा रु. 10,000 के गुणांक में बढाकर बोली लागनी होगी।
- राज्य में शहरीय क्षेत्र जयपुर शहर में 05, जोधपुर में 02, उदयपुर में 02, माउन्ट आबू व आबूरोड एवं अन्य शहरों में एक-एक मॉडल शॉप आवंटित की जायेगी।
- मॉडल शॉप की न्यूनतम रिजर्व प्राईस जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, माउन्ट आबू तथा आबूरोड के लिये राशि रुपये 6 करोड प्रति मॉडल शॉप तथा अन्य शहरों के लिये राशि रुपये 50 लाख प्रति मॉडल शॉप निर्धारित है।
- बोलीदाता एक बार में रिजर्व प्राइस / पिछ्ठी बोली से 10 प्रतिशत से अधिक राशि बढाकर बोली नहीं लगा सकेगा।
- ऑनलाईन नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रति मॉडल शॉप का आवेदन शुल्क रुपये 50,000/- निर्धारित है, जो की अपरिहय (Non-refundable) होगा।
- मॉडल शॉप्स का जितेवार एवं उनके आवेदन शुल्क, न्यूनतम रिजर्व प्राईस एवं अमानत राशि का विवरण विभागीय वेबसाईट <https://iems.raajasthan.gov.in> पर उपलब्ध रहेगा।
- ऑनलाईन नीलामी में SSOD के माध्यम से भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदक द्वारा मॉडल शॉप का चयन कर आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि यथासंभव नीलामी की तिथि से एक दिवस पहले रात 11.59 तक <https://iems.raajasthan.gov.in> पर वेबसाईट पर बोलीदाता के ऑनलाईन भुगतान द्वारा इस वेबसाईट पर जमा हो जानी चाहिये। ऐसा करने से बोलीदाता विभिन्न प्रकार की तकनीकी समस्याओं से बच सकेगा। ऑनलाईन भुगतान नहीं होने या अन्यथा तकनीकी कारणों से निर्धारित राशिवाय जमा नहीं होने के कारण बोली में भाग नहीं ले पाने के लिये आवेदक स्वयं जिम्मेवार होगा।
- प्रत्येक मॉडल शॉप के लिये ऑनलाईन नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित न्यूनतम रिजर्व प्राईस की 2 प्रतिशत राशि अमानत राशि के रूप में आवेदन के साथ जमा करानी होगी। बिड राशि के अनुसार अतिरिक्त अमानत राशि (Dynamic Earnest Money) भी जमा करानी होगी।
- सफल बोलीदाता को धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारंटी राशि एवं वार्षिक लाईसेन्स ई-नीलामी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तों, नीलामी वेबसाईट पर उपलब्ध है के अनुसार जमा करनी होगी।
- निष्पत्ति समय में वांछित राशिवाय यथा-धरोहर राशि, स्वीकृत वार्षिक गारंटी राशि एवं वार्षिक लाईसेन्स फीस जमा न कराने पर स्वीकृति निरस्त कर समस्त जमा राशि खारिज की जायेगी।
- वर्ष 2025-26 के पात्र अनुभवाधारियों को वर्ष क्रमांक: 2026-27, 2027-28 व 2028-29 के लिये निर्धारित शर्तों पर अनुभवाप नीलामी का अवसर दिया जायेगा।
- एसीबी के महानिदेशक के मुताबिक एबीसी हनुमानगढ़ चौकी के शिकायत मिली थी कि मोकलसर सरपंच गणेशराम गोदारा पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारी के पिता के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि स्वीकृत करवाने के बदले 12,000 रुपए रिश्तत मांग रहा था। शिकायत की सत्यता जांचने के बाद एसीबी ने जाल बिछाया और सरपंच गणेशराम को 10,000 रुपए रिश्तत लेते मौके पर गिरफ्तार किया था।
- एसीबी के महानिदेशक के मुताबिक एबीसी हनुमानगढ़ चौकी को शिकायत मिली थी कि मोकलसर सरपंच गणेशराम गोदारा पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारी के पिता के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि स्वीकृत करवाने के बदले 12,000 रुपए रिश्तत मांग रहा था। शिकायत की सत्यता जांचने के बाद एसीबी ने जाल बिछाया और सरपंच गणेशराम को 10,000 रुपए रिश्तत लेते मौके पर गिरफ्तार किया था।
- राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बने नियम के अनुसार रहेगी।

(आबकारी नकलते)
DIPR/C/8151/202025

आर.पी.एस.सी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा के खिलाफ चलेगा ट्रायल

एसओजी ने ईडी मामलों की विशेष अदालत में पेश की अभियोजन स्वीकृति की प्रति

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर।द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती- 2022 पेपर लीक मामले में एसओजी ने ईडी मामलों की विशेष अदालत में आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति की प्रति पेश की।

कटारा को एसओजी ने 18 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार किया था। कटारा पर आरोप है कि वह आयोग से पेपर अपने घर ले गया था। वहां उसने अपने भांजे विजय डामोर की मदद से पेपर को रजिस्टर में उतारा। बाद में पेपर 60 लाख में सरगना अनिल मीणा को बेच दिया। मीणा ने 80 लाख में पेपर भूपेन्द्र सारण को बेच दिया। एसओजी ने कटारा सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। बाद में ईडी की ओर से प्रकरण दर्ज करने पर मामले को सुनवाई के लिए ईडी कोर्ट भेजा गया। लेकिन

अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने के कारण मामले में कटारा के खिलाफ ट्रायल नहीं चल पा रहा था। लेकिन सरकार ने कुछ दिन पहले ही कटारा के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी करने की अनुमति दी थी।

चलती बस में पेपर हल करवा रहे थे

पेपरलीक के सरगना चलती बस में अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले पेपर हल करवा रहे थे। लेकिन उदयपुर जिले के बेकरिया थाना पुलिस ने 24 दिसम्बर 2022 को इस बस को पकड़ा था। बस में द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के 49 अभ्यर्थी परीक्षा से पहले पेपर हल कर रहे थे। इसके बाद पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। एसओजी के अनुसार कटारा को इस

परीक्षा के पेपर और उत्तर कुंजी तैयार करने का दायित्व मिला था। लेकिन उसने पेपरलीक कर दिया। कटारा के घर से 51.20 लाख रुपए नकद व 541 ग्राम सोने के 9 आभूषण बरामद हुए थे।

30 जून को होगी मामले की सुनवाई

एसओजी की ओर से विशेष लोक अभियोजक बीएस चौहान की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर आरोपी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी करने वाले कार्मिक विभाग के अधिकारी को भी अभियोजन पक्ष का गवाह बनाने की अनुमति मांगी है। अदालत मामले में तीस जून को सुनवाई करेगी।

पुलिसकर्मियों ने किया योगाभ्यास

जयपुर। अंतरराष्ट्रीय योग सप्ताह में शुक्रवार को पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों ने योगाभ्यास किया।पुलिस कमिश्नरेट में ब्रह्मकुमारी संस्थान के योग प्रशिक्षकों ने योगाभ्यास करवाया। योगाभ्यास को बढ़ावा देने के लिए पुलिसकर्मियों को योगाभ्यास करवाकर मानसिक तनाव दूर करने का प्रयास किया गया। योग भारतीय परम्परा एवं संस्कृति की विश्व को अनुपम देन है। प्राचीन भारतीय षड्विंशत्य शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य को लेकर हमारी सभी की आवश्यकताओं का सम्पूर्ण जवाब है। पुलिसकर्मियों में विषम परिस्थितियों में कार्य करने को लेकर शारीरिक एवं मानसिक तनाव को दूर करने में योगाभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस अवसर पर पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) देवेन्द्र कुमार विश्नोई, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) शिल्पा चौधरी सहित पुलिस अधिकारी व पुलिसकर्मी उपस्थित थे।

स्व. विजय रूपाणी हम सभी के लिए प्रेरणास्त्रोत : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को गांधी नगर पहुंचकर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. विजय रूपाणी को श्रद्धांजलि अर्पित की।

गांधीनगर/जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को गांधीनगर में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. विजय रूपाणी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने रूपाणी के देहावसान पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि

उन्होंने पार्षद, मेयर से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में समर्पित होकर काम किया, जो हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। उनका निधन पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत पुण्यात्मा को अपने परम धाम में स्थान देने की प्रार्थना की तथा शोक

नशीली कोल्डड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म

जयपुर। नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर परिचित युवक द्वारा कार में एक महिला से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। विरोध करने पर गाली-गलौच कर मारपीट की। भांकरोटा थाने में पीड़ित महिला ने आरोपी परिचित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मामले की जांच थानाधिकारी मनीष गुप्ता कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि भांकरोटा इलाके में रहने वाली महिला ने मामला दर्ज करवाया कि परिचित होने के कारण आरोपी से उसकी बातचीत थी। आरोप है कि भांकरोटा जाने के दौरान उसे आरोपी परिचित मिला। बातचीत के दौरान आरोपी ने उसके अपनी कार में बैठा लिया। कार में बैठाकर आरोपी परिचित ने उसे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए ऑफर की। कोल्ड ड्रिंक में नशा मिला होने के कारण बेहोशी छाने लगी। बेहोशी की हालत में आरोपी ने कार में ही उसके साथ रेप किया।

ऑनलाइन ठगी के आरोपियों को जश्न नहीं मनाने की शर्त पर जमानत

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने ऑनलाइन ठगी के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे दो आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने दोनों आरोपियों पर शर्त लगाई है कि वे जमानत पर रिहा होने के बाद सार्वजनिक रूप से जश्न नहीं मनाएंगे।

अदालत ने कहा कि, यदि आरोपी सार्वजनिक रूप से जश्न करते मिले तो राज्य सरकार उनकी जमानत को रद्द करने के लिए याचिका दायर कर सकती है। जस्टिस गणेश राम मीणा की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश सौरभ और सौरभ गोस्वामी की जमानत याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए। जमानत याचिकाओं में अदालत को बताया गया कि प्रकरण में आरोपियों को झूठा फंसाया है। याचिकाकर्ता बीते

25 मार्च से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। पुलिस ने प्रकरण में विस्तृत जांच कर आरोप पत्र भी संबंधित अदालत में पेश कर दिया है। जिसकी सुनवाई पूरी होने में समय लगने की संभावना है। ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ताओं पर ऑनलाइन ठगी करने का गंभीर आरोप है। इसके साथ ही अदालत के सामने आया कि यदि आरोपियों को जमानत दी गई तो ये सार्वजनिक रूप से अपनी रिहाई का जश्न मनाएंगे। मामले की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश देते हुए उन्हें सार्वजनिक रूप से जश्न नहीं मनाने को कहा है। गौरतलब है कि करीली निवासी इन आरोपियों पर गत मार्च माह में स्थानीय थाने में ऑनलाइन ठगी का मामला दर्ज कराया गया था।

दो लोगों से 7 लाख रुपए की साइबर ठगी

जयपुर। शहर में दो अलग-अलग थाना इलाके में दो लोगों से सात लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी है। जवाहर नगर थाना इलाके में साइबर ठगी ने एक युवक के फोन पे एप को हैक कर उसके खाते से 2 लाख रुपए निकाल लिए। पुलिस के अनुसार जवाहर नगर निवासी नानकराम ने मामला दर्ज करवाया कि साइबर ठगी ने उसके खाते से पांच लाख रुपए निकाल लिए। यह ठगी 19 जून को हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जांच में सामने आया कि ठगी ने उसके मोबाइल को हैक किया था और फिर उसके खाते से यह राशि निकाल ली गई। दूसरी घटना में करधनी थाना इलाके में साइबर ठगी ने एक युवक के फोन पे एप को हैक कर उसके खाते से 2 लाख रुपए निकाल लिए। पुलिस के अनुसार निवासी एनक्लेव आर्मी कैम्प निवासी धनवंश कुमार ने मामला दर्ज करवाया कि किसी ने उसके फोन पे एप को हैक कर लिया और फिर उसके खाते से ऑनलाइन दो लाख रुपए निकाल लिए गए।

‘स्वस्थ तन-मन के लिए योग जरूरी’

जयपुर । राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने शुक्रवार को सेंट्रल पार्क में स्वयं योग करके आम जन को योग क्रियाएं करवाईं। उन्होंने युवाओं और 50 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए योग और गति से जुड़ी विभिन्न शारीरिक मुद्राओं का प्रदर्शन कर प्रतिदिन इन्हें कर स्वस्थ जीवन जीने का संदेश दिया।

उन्होंने कहा कि योग हजारों साल से चली आ रही हमारी संस्कृति है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए 21 जून को इसलिए चुना गया की वर्ष के 365 दिन में यह सबसे बड़ा दिन होता है। उन्होंने कहा कि मूलतः योग भारत का है। महर्षि पतंजलि ने इसकी शुरुआत की। जो योग नियमित करता है, वह जीवन पर्यंत स्वस्थ रहता है और उसकी आयु बढ़ती है।

राज्यपाल ने शुक्रवार को सेंट्रल पार्क में राजस्थान कॉर्पोरेटिव फेडरेशन, सरस डेयरी द्वारा आयोजित सामूहिक योग एवं स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम में भाग लेने के साथ ही योग शिक्षकों, कलाकारों और योग शिक्षण से जुड़े प्रतिभावान बच्चों को प्रशस्ति पत्र और अपनी ओर से नकद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित भी किया।

इस अवसर पर उद्योग, खेल एवं

■ योग हजारों सालों से चली आ रही हमारी संस्कृति है : बागडे

युवा मामले विभाग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि योग मन, बुद्धि और शरीर की एकता स्थापित करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लगातार काम करते हैं और इसकी प्रेरणा योग को बताते हैं। उन्होंने कहा कि भागमभाग की इस जिंदगी में योग से ही स्वस्थ रहा जा सकता है।

विधायक गोपाल शर्मा ने योग की भारतीय परंपरा और योगेश्वर श्री कृष्ण की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सीमा पर आतंकवाद के ठिकाने नष्ट करने को महती बताते हुए कहा कि यह भी योग से संभव हुआ।

आरंभ में महाप्रबंधक श्रुति भारद्वाज ने स्वागत उद्घोषण में सरस की गतिविधियों और योग संस्कृति के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में अवगत कराया। सरस डेयरी के अध्यक्ष ओमप्रकाश पुनिया भी उपस्थित रहे। इससे पहले तन्मय सिंह राव और अंकुश ने दुर्लभ योग मुद्राओं का प्रदर्शन किया। डॉ. महेंद्र सिंह राव के नेतृत्व में लोगों ने सामूहिक योग, व्यायाम भी किया।

सी.ए.जी. द्वारा गठित ‘वर्किंग ग्रुप’ में आई.ए.एस. संदीप वर्मा भी शामिल

जयपुर । भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) ने सार्वजनिक खरीद की व्यवस्था में सुधार लाने और इसकी ऑडिट में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी पक्षकारों के साथ मिलकर एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया है। इस समूह में पूरे देश में सिर्फ राजस्थान कैंडर के वरिष्ठ आई.ए.एस. और अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा को शामिल किया गया है।

गौरतलब है कि इस सात सदस्यीय समूह में अतिरिक्त उप नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (ए.डी.ए.आई) प्रमोद कुमार, राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा, राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लि. के पूर्व सीईओ प्रकाश गौड़, नीति आयोग के कार्यक्रम निदेशक पार्थ साथी रेड्डी, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सी.ई. शैलेन्द्र सिंह, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम के सीएफओ पी.के.अग्रवाल, आर्थिक सलाहकार के. सुब्रमण्यम शामिल होंगे। यह समूह सार्वजनिक खरीद



आई.ए.एस. संदीप वर्मा

प्रक्रिया के मौजूदा नियम-कायदों के अभाव अथवा ऑडिट के दौरान

- यह 7 सदस्यीय समूह सार्वजनिक खरीद की व्यवस्था में सुधार लाने और इसकी ऑडिट में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए काम करेगा
- राजस्थान कैंडर के अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा, पूरे देश में इकलौते आई.ए.एस.अफसर हैं, जो इस समूह का हिस्सा बने हैं।

पाई गई खामियों को अंगीकृत करेंगे, ताकि सरकार उन्हें दुरुस्त कर सके। क्या खरीद होनी चाहिए और किस प्रकार से होनी चाहिए, इस बारे में भी सही सलाह और सिफारिश भी पेश करेंगे। अंकेक्षण (ऑडिट) के दौरान

दुनियाभर में अपनाई जा रही सर्वोत्तम नीतियों अथवा प्रथाओं को सी.ए.जी. के ऑडिटर्स की ट्रेनिंग में भी लागू करने का सुझाव देंगे। यह ग्रुप प्रत्येक 3 माह में एक बार रिव्यू मीटिंग बुलायेगा।

खान विभाग ने ढाई माह में सर्वाधिक 1 6 7 0 करोड़ रुपए राजस्व कमाया

मुख्यमंत्री भजन लाल के नेतृत्व में खनिज खोज में ए.आई. के उपयोग का पायलट प्रोजेक्ट

जयपुर । खान एवं भूविज्ञान विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 17 जून तक 1670 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ है, जो इसी अवधि का अब तक का सर्वाधिक राजस्व है।

उन्होंने विभागीय गतिविधियों में पारदर्शिता लाने की दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए माइनिंग से जुड़ी सभी एप्लीकेशंस को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी को भी कार्य विशेष के लिए विभाग के कार्यालयों में अनावश्यक नहीं आना पड़े। शुक्रवार को प्रमुख सचिव टी. रविकान्त उदयपुर खनिज भवन में हाईब्रिड मोड पर विभागीय अधिकारियों की बैठक ले रहे थे।

उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा माइनिंग प्लान के ऑन लाईन अनुमोदन की व्यवस्था कर दी है इसी तरह से लीज इन्फोर्मेशन और डिमाण्ड सिस्टम की संपूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन करने से समय व धन की बचत के साथ ही खानधारकों को बड़ी राहत मिलने लगी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के निर्देशन में अब



खान एवं भूविज्ञान विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने शुक्रवार को उदयपुर के खनिज भवन में हाईब्रिड मोड पर विभागीय अधिकारियों की बैठक ली।

पायलट आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग सिस्टम का उपयोग मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए शुरू किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों का विश्लेषण कर इसे और अधिक विस्तारित किया जाएगा। इसी तरह से डीएमएफटी को और अधिक व्यावहारिक बनाते हुए खनन प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, कोषल

विकास, महिला बाल विकास सहित सीधे आम आदमी से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी है।

रविकान्त ने खनिज प्लाट और ब्लॉक तैयार करने के डेलिनिवेशन व अन्य कार्यों के निष्पादन में तेजी लाने के साथ ही माइनिंग व जियोलोजी विंग में बेहतर समन्वय पर जोर दिया ताकि अधिक से अधिक माइनर व मेजर

मिनरल के ब्लॉक तैयार कर ऑक्शन किया जा सके। इससे माइनिंग सेक्टर में निवेश, रोजगार और राजस्व की बढ़ोतरी तो होगी ही साथ ही अवैध खनन पर भी रोक लग सकेगी। उन्होंने

- सभी एप्लीकेशंस होगी ऑनलाइन- पारदर्शिता, समय व धन की होगी बचत : टी. रविकांत
- अधिक से अधिक मिनरल प्लाटों के डेलिनिवेशन कर ऑक्शन पर जोर

पुरानी व करन्ट बकाया राशि की वसूली के और अधिक कारगर प्रयास करने को कहा।निदेशक माईस दीपक तंवर ने कहा कि अधीक्षण खनि अभियंता स्तर पर राजस्व वसूली, डेलिनिवेशन, प्लॉट ऑक्शन, आरसीसी/ईआरसीसी ठेकों की नीलामी व रायल्टी वसूली आदि प्रमुख बिन्दुओं पर नियतकालीन समीक्षा होनी चाहिए।

उन्होंने खान धारक पर सरकारी राजस्व की बकाया द्यु होते ही उसे जमा करने का नोटिस चले जाना चाहिए ताकि समय पर राजस्व आ सके।

तंवर ने विश्वास दिलाया कि विभाग द्वारा राज्य सरकार द्वारा तय

राजस्व लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने फील्ड अधिकारियों से कहा कि राजस्व लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय वर्ष के अंतिम महिनों तक प्रतीक्षा करने के स्थान पर निर्धारित

लक्ष्यों के अनुसार प्रतिमाह वसूली की जाये।समीक्षा बैठक में न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों, विधानसभा के लंबित प्रकरणों, मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव वसूली, डेलिनिवेशन, प्लॉट ऑक्शन, आरसीसी/ईआरसीसी ठेकों की नीलामी व रायल्टी वसूली आदि प्रमुख बिन्दुओं पर नियतकालीन समीक्षा होनी चाहिए।

बैठक में संयुक्त सचिव आशु चौधरी, ओएसडी श्रीकृष्ण शर्मा, एसजी सुनील वर्मा, जेएलआर गजेन्द्र सिंह, विभाग के अतिरिक्त निदेशक माईनिंग और भूविज्ञान, अधीक्षण खनिज अभियंता, एमई-एमई व अधीक्षण भूवैज्ञानिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

